सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 141, नई दिल्ली । गुरुवार, 01 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

इंसान की नीयत अगर साफ नहीं तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे छोटा ही रहेगा।

03 हाईकोर्ट ने छात्रों की मौत पर एमसीडी समेत पुलिस को लगाई फटकार
06 आज के शैक्षणिक माहौल में बहुविषयक शिक्षा का महत्व
08 मन को सत्संग से ही आराम मिलेगा स्वामी रामप्रकाश

दिल्ली मेट्रो: रेड लाइन के पांच किलोमीटर हिस्से पर होगा स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल का परीक्षण

संजय बाटला

डीएमआरसी स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम विकसित करने में जुट गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से परियोजना पर काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन के पांच किलोमीटर हिस्से तक होगा। बता दें इससे पहले मजेंटा व पिंक लाइन पर इसका इस्तेमाल हुआ है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल (डीएमआरसी) सिग्नल सिस्टम विकसित करने में जुटा हुआ है। डीएमआरसी व बीईएल (भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड) दोनों मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल का परीक्षण दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन के पांच किलोमीटर हिस्से पर होगा।

रेड लाइन पर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल (एटीसी) सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा समय में सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल मजेंटा व पिंक लाइन पर किया गया है। इस वजह से इन दोनों कॉरिडोर पर चालक रहित पूरी तरह स्वचालित मेट्रो का परिचालन होता है।

इन दोनों कारिडोर पर विदेश से लिए गए सीबीटीसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी महंगा है। अभी स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका लैब शास्त्री पार्क में मेट्रो के प्रशिक्षण संस्थान में है।

रेड लाइन पर शाहदरा से शास्त्री पार्क के बीच का मेट्रो कॉरिडोर

डिजिटल ट्रैक सर्किट सतत स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली से लैस किया जाएगा। दो मेट्रो ट्रेनों को भी सीबीटीसी सिग्नल से परिचालन के लिए तैयार करने की पहल की गई है। इसके तहत दो ट्रेनों के हार्डवेयर व साफ्टवेयर में भी बदलाव होगा। ट्रायल के पहले डीएमआरसी किसी तीसरी एजेंसी से स्वतंत्र रूप से सुरक्षा मूल्यांकन कराएगी।

इसके मद्देनजर डीएमआरसी (DMRC) ने सुरक्षा मूल्यांकन के लिए एक एजेंसी की सेवा लेने की पहल की है। यह एजेंसी स्वतंत्र रूप से सुरक्षा मूल्यांकन कर डीएमआरसी को रिपोर्ट और अहम सुझाव देगी। इसके बाद शाहदरा से शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के बीच व शास्त्री पार्क डिपो सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम का परीक्षण होगा।

रेड लाइन पर रात में मेट्रो का परिचालन समाप्त होने के होगा परीक्षण

शाहदरा से शास्त्री पार्क के बीच चार मेट्रो स्टेशन हैं। जिसमें इन दोनों स्टेशनों के अलावा वेलकम, सिलमपुर शामिल है। परीक्षण रेड लाइन पर रात में मेट्रो का परिचालन समाप्त होने के बाद होगा। परीक्षण के दौरान दो ट्रेनें स्वचालित ट्रेनों की तरह शाहदरा से शास्त्री पार्क के बीच स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल की मदद से चलेंगी।

डीएमआरसी को उम्मीद है कि अगले वर्ष के अंत तक स्वदेशी सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। इससे आने वाले समय में स्वदेशी सिग्नल सिस्टम से चालक रहित मेट्रो ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्तूबर 2025 तक हो जाएगा पूरा, नितिन गडकरी ने संसद को बताया

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्तूबर, 2025 तक पूरा हो जाएगा। बुधवार को संसद को इस बारे में जानकारी दी गई।

नई दिल्ली। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने 1,386 किलोमीटर की लंबाई वाले 53 पैकेजों में स्पर्स सहित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू कर दिया है।

गडकरी ने कहा, "जून 2024 तक, कुल 26 पैकेज पूरे हो चुके हैं।" उनके अनुसार, कार्य की भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और कुल 1,136 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका है।

उन्होंने कहा, "संशोधित निर्धारित पूर्णता तारीख (कंप्लीशन डेट) अक्तूबर, 2025 है।" यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, इसके प्रभाव में दिल्ली से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) की दूरी में लगभग 180 किलोमीटर की कमी और जुड़े हुए गंतव्यों तक यात्रा के समय में 50 प्रतिशत तक की कमी शामिल है। एक अलग सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि 30 जून, 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 983 यूजर फीस प्लाजा काम कर रहे हैं।

झमाझम बारिश से कई जगहों पर जलभराव, दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम; येलो अलर्ट

दिल्ली में वर्षा के यलो अलर्ट के बावजूद उमस भरी गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ाया। वहीं बुधवार देर शाम हुई बारिश से आमजन को राहत मिली है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2012 के बाद पहली बार 39 डिग्री पार पारा पहुंचा। अगले दो-तीन दिन बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

नईदिल्ली। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को एक बार फिर मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित होने के बाद आज देर शाम जोरदार बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी सहित आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में तेज बारिश हो रही हैं। दिल्ली में कई जगहों पर सड़कें लबालब हो गई हैं।

तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। इस कारण लोग परेशान हो रहे हैं।

इससे पहले हल्की से मध्यम वर्षा के कारण यलो अलर्ट में दिनभर तेज धूप निकली रही। उमस से लोगों का हाल बेहाल रहा तो जुलाई माह के आखिरी हफ्ते में अधिकतम तापमान नया रिकॉर्ड बनाते हुए 39 डिग्री पार चला गया।

अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बुधवार से अगले तीन दिनों तक दिल्ली में अच्छी वर्षा हो सकती है। ऐसी संभावना जताई थी। इसी कारण बुधवार के लिए आरेंज जबकि उसके बाद अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

IMD ने बादल छाए रहने की जताई थी संभावना

मौसम विभाग (IMD Alert) का पूर्वानुमान था कि बुधवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा एवं कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि बादल तो छाए नहीं रहे लेकिन बारिश जरूर हुई।

तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड

मंगलवार को सुबह से ही धूप निकल गई थी, दिन चढ़ने के साथ-साथ यह और तीखी होती गई। इससे उमस भी बढ़ी और तापमान में भी इजाफा देखने को मिला। अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 39.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

नया डायवर्जन प्लान लागू: जीटी रोड पर दादरी की तरफ भारी वाहनों की नो एंट्री, लालकुआं से सीमापुरी बॉर्डर के बीच टेंपो भी बंद

जीटी रोड पर दादरी की तरफ भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। अब ये वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) के जरिए जा रहे हैं। उधर लालकुआं से सीमापुरी बॉर्डर के बीच टेंपो का संचालन भी बंद कर दिया गया है। बताया गया कि यह डाइवर्जन प्लान दो अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगा।

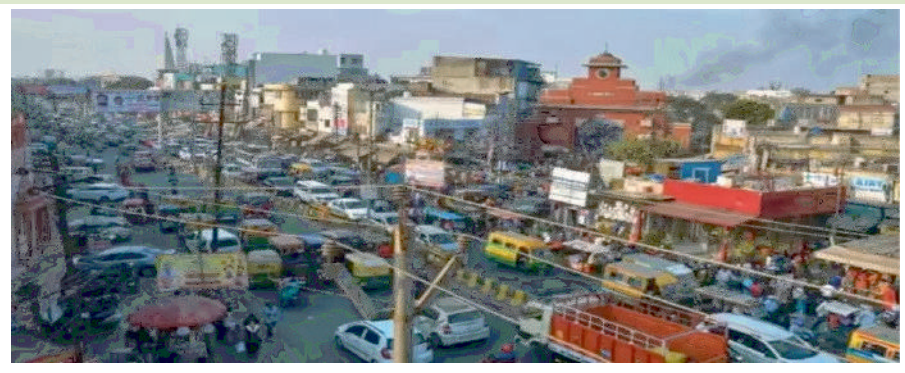

गाजियाबाद। मंगलवार से जीटी रोड पर लाल कुआं की तरफ से दादरी की तरफ भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई। इन वाहनों को डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड के जरिए सिकंद्राबाद की तरफ भेजा जा रहा है। बताया गया कि यातायात पुलिस ने बुधवार की आधी रात से प्रभावी होने वाला नया डायवर्जन प्लान भी जारी किया है।

शिवरात्रि पर दूधेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ियों की भारी भीड़ आने की वजह से बुधवार रात 12 बजे से चौधरी मोड़ और हापुड़ तिराहे और हापुड़ तिराहे से घंटाघर की तरफ वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर भी इस दौरान बंद रहेगा। लाल कुआं से सीमापुरी बॉर्डर के बीच टेंपो का संचालन बंद कर दिया गया है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, डाइवर्जन प्लान दो अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगा। पुलिस ने मंगलवार को एनएच-नौ से लाल कुआं पर बुलंदशहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बेरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया। हल्के वाहनों को निकाला जा रहा था।

वाहन पार्किंग व्यवस्था यहां रहेगी

पुलिस के मुताबिक, जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हापुड़ रोड की तरफ से आने वाले वाहन सेठ मुकंदलाल स्कूल में खड़ा कर मंदिर तक श्रद्धालु पैदल आएंगे।

पुलिस के अनुसार, जीटी रोडपर घंटाघर की तरफ से आने वाले श्रद्धालु घंटाघर रामलीला मैदान में वाहन खड़ा करेंगे। विजय नगर की तरफ से आने वाले वाहन चालक चांदमारी में मिलिट्री मैदान में वाहनों की पार्किंग करेंगे।

दूधेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में वाहनों का आवागमन मंदिर के आसपास पूरी तरह बंद रहेगा। - पीयूष कुमार

एनसीआर में गाड़ियों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, बुधवार आधी रात से नया डाइवर्जन

कांवड़ यात्रा के कारण बुधवार आधी रात से हल्के वाहनों के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू होगा। आने वाले समय में कई मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी होने वाली हैतो कई स्थानों पर वाहनों को घूमकर लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। डाइवर्जन प्लान दो अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों पर असर पड़ रहा है।

गाजियाबाद। शिवरात्रि पर दूधेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ियों की भारी भीड़ आने की वजह से यातायात पुलिस ने नया डाइवर्जन प्लान जारी किया है। बुधवार रात 12 बजे से चौधरी मोड़ और हापुड़ तिराहे और हापुड़ तिराहे से घंटाघर की तरफ वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर भी इस दौरान बंद रहेगा। लाल कुआं से सीमापुरी बॉर्डर के बीच टेंपो का संचालन नहीं होगा। जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालु सेठ मुकंदलाल स्कूल, घंटाघर रामलीला मैदान और चांदमारी में मिलिट्री मैदान में वाहनों की पार्किंग रहेगी। डाइवर्जन प्लान दो अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगा।

इससे पहले सावन माह में प्रतिवर्ष भोले के भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के लिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एनसीआर के जिलों में प्रशासन रूट डायवर्जन के साथ ही तमाम मार्गों पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर देता है। इससे न सिर्फ रोजाना आने-जाने वाले नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उद्योग धंधे, बच्चों की पढ़ाई और व्यवसाय पर भी असर पड़ता है।

परेशानी से लोगों को मिल सकेगी निजात

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ (एनएच-नौ) के चौड़ीकरण के बाद यह उम्मीद जगी थी कि साल-दर साल होने वाली इस परेशानी से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन अफसर ऐसा कोई विकल्प तलाश नहीं सके, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुए बिना भोले के भक्तों की यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके।

ग्रीन लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: आज के दौर में लॉजिस्टिक्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

डॉ. अंकुर शरण

आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने लॉजिस्टिक्स उद्योग में क्रांति ला दी है। ये दोनों प्रौद्योगिकियां न केवल उद्योग की दक्षता बढ़ा रही हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

ग्रीन लॉजिस्टिक्स क्या है और क्यों जरूरी है?

ग्रीन लॉजिस्टिक्स का लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रक्रियाओं को अधिक स्थायी बनाना है। यह ऊर्जा की खपत को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने, और पुनः उपयोग व पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों का अधिक उपयोग करने पर जोर देता है।

ग्रीन लॉजिस्टिक्स के लाभ:

पर्यावरण संरक्षण: ग्रीन लॉजिस्टिक्स से वायु, जल, और भूमि प्रदूषण में कमी आती है, जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है।

लागत में कमी: संसाधनों का कुशल उपयोग करने से परिचालन लागत में कमी आती है।

ब्रांड इमेज में सुधार: पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाने वाली कंपनियों की छवि बेहतर होती है, जिससे वे अधिक ग्राहक आकर्षित कर पाती हैं।

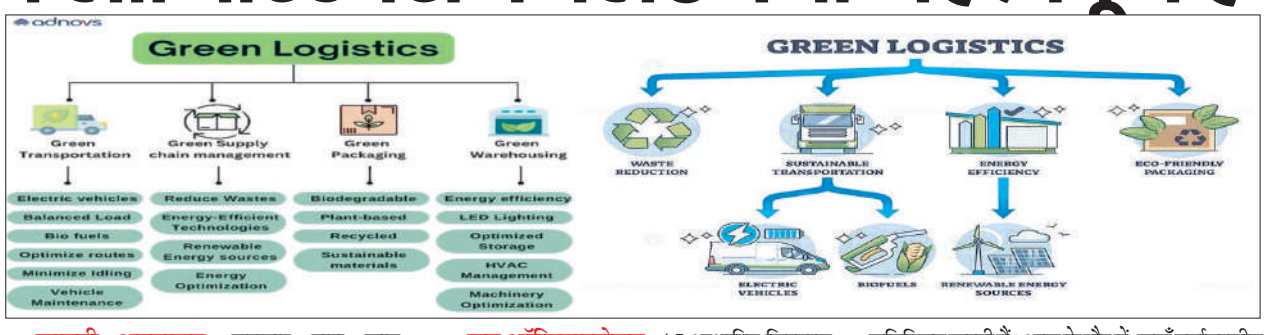

कानूनी अनुपालन: सरकार द्वारा लागू पर्यावरणीय नीतियों का पालन करते हुए कंपनियाँ कानूनी समस्याओं से बच सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का योगदान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लॉजिस्टिक्स उद्योग में कार्यकुशलता और सटीकता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। AI डेटा विश्लेषण, भविष्यवाणी, और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिससे लॉजिस्टिक्स संचालन में सुधार होता है।

AI के लाभ:

डेटा एनालिटिक्स: AI की मदद से कंपनियाँ डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं और मांग की सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होता है।

रूट ऑप्टिमाइजेशन: AI आधारित सिस्टम्स ट्रांसपोर्टेशन रूट्स का अनुकूलन करते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है।

स्वचालन: वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में रोबोटिक्स और AI तकनीक का उपयोग करके कार्यों को स्वचालित किया जा रहा है, जिससे मानव त्रुटियों में कमी आती है और दक्षता बढ़ती है।

ग्राहक सेवा: AI चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ग्राहकों को त्वरित और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

ग्रीन लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रौद्योगिकियां न केवल संचालन में सुधार करती हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करती हैं। आज के दौर में, जहाँ पर्यावरणीय समस्याएँ और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हैं, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और AI का उपयोग करना न केवल एक स्मार्ट व्यवसायिक निर्णय है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है।

डॉ. लॉजिस्टिक्स एक पहल है जो पाठकों को लॉजिस्टिक्स उद्योग की गहरी समझ प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य है उद्योग के विभिन्न पहलुओं, कार्यों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना, ताकि लोग इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं और अवसरों को समझ सकें। यह पाठकों को लॉजिस्टिक्स के महत्व और इसकी जटिलताओं से अवगत कराकर उद्योग में उनकी समझ और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है।

ankur.supplychain@gmail.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

एचआईवी से कितना अलग है एड्स, डॉक्टर ने बताए इस खतरनाक बीमारी से जुड़े सभी सवालों के जवाब

हाल ही में सामने आए संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चला कि दुनियाभर में करीब 4 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं। इतना ही नहीं इनमें से 90 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वायरस के खिलाफ इलाज नहीं मिल जाता है। खुद भारत में लगभग 23 लाख से इस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस खतरनाक वायरस (HIV vs. AIDS) के बारे में जानकारी हो।

नई दिल्ली। देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में HIV के बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। बीते दिनों सामने आई त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (TSACS) की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में साल अप्रैल 2007 से मई 2024 तक कुल 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं इस गंभीर वायरस को लेकर सामने आए संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में खुलासा हुआ कि दुनियाभर में लगभग 4 करोड़ लोग HIV पॉजिटिव हैं।

भारत में डराने वाले आंकड़े

यह आंकड़े बेशक डराने वाले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि HIV पॉजिटिव इन लोगों में करीब 90 लाख लोगों को इस वायरस के खिलाफ इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हर मिनट एड्स के कारण एक व्यक्ति की मौत हो रही है। अकेले भारत में 23 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के हैं।

ऐसे में HIV और एड्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने सी के बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम में आब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की डायरेक्टर डॉ. आस्था दयाल से बातचीत की।

एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है?

डॉक्टर आस्था बताती हैं कि एचआईवी (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) एक वायरस है, जो CD4 या टी-सेल्स को टारगेट करता है, जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जरूरी है। अगर समय रहते इलाज न किया जाए, तो एचआईवी धीरे-धीरे इम्युनिटी को खत्म कर सकता है।

वहीं, HIV संक्रमण का सबसे लास्ट स्टेज AIDS कहलाता है। यह एक गंभीर स्थिति में जिसमें हमारे शरीर में फाइटर सेल्स यानी WBC की संख्या बहुत कम हो जाती है और फिर इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। आसान शब्दों में समझें तो एचआईवी आगे चलकर एड्स में बदल जाता है, जो एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है।

इसके लक्षण क्या है?

एचआईवी के लक्षण और संकेत

शुरुआती चरण में एक्यूट एचआईवी संक्रमण में बुखार, गले में खराश, दाने, लिम्फ नोड्स में सूजन और मांसपेशियों में दर्द आदि फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। वहीं, इसके क्रोनिक स्टेज (क्लिनिकल लेटेंसी) में वायरस अभी भी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, भले ही इसमें कोई लक्षण नजर न आते तो, तब भी।

एड्स के लक्षण

निमोनिया
रात में पसीना आना
वजन में तेजी से कमी
लंबे समय तक दस्त रहना
लंबे समय तक बुखार रहना
जेनिटल्स या मुंह के घाव होना
न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जैसे मेमोरी लॉस
त्वचा पर धब्बे जो लाल, भूरे, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं।

शरीर को कैसे प्रभावित करता HIV?

डॉक्टर बताते हैं कि सीडी4 यानी टी-सेल्स संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम की क्षमता के लिए जरूरी हैं, लेकिन एचआईवी इन सीडी4 सेल्स को टारगेट करता है और शरीर पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें खत्म कर देता है। इन सेल्स में कमी की वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर संक्रमण और कुछ प्रकार के कैंसर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है।

ऐसे में इलाज के बिना लंबे समय तक रहने की समय से HIV, एड्स में विकसित हो जाता है, जो एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें शरीर का डिफेंस मेकेनिज्म गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और संक्रमण होते हैं।

HIV से बचाव कैसे करें?

एड्स से बचने के लिए जरूरी है कि HIV से अपना बचाव किया जाए और इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

सुरक्षित यौन संबंध के लिए कंडोम का इस्तेमाल करें।

समय-समय पर अपना टेस्ट करवाएं और सुनिश्चित करें कि आपका पार्टनर भी एचआईवी से बचाव के लिए टेस्ट करवाएं।

सुई या अन्य नशीली दवाओं के सीरिंज साझा करने से बचें।

प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या PrEP एक दवा है, जो हाई रिस्क वाले व्यक्तियों में इन्फेक्शन के खतरे को कम करती है।

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) प्रेग्नेंट महिलाओं में विकासशील बच्चे में एचआईवी फैलने से रोक सकती है।

देश-विदेश में मशहूर है पीलीभीत की बांसुरी, असम से आता है बांस और इसे बनाने का तरीका है बेहद खास

बांसुरी के नाम से श्रीकृष्ण की मूरत सबसे पहले सामने आती है। बांसुरी दुनिया के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। बांस से बनी बांसुरी से निकलने वाले सुर मनोरंजन के साथ माइंड को रिलैक्स भी करते हैं। इस खास वाद्य यंत्र को पीलीभीत में बनाया जाता है और ये देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है।

नई दिल्ली। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर पीलीभीत वैसे तो बाघों के लिए लिए मशहूर है, लेकिन यह जगह दुनियाभर में बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नामी-गिरामी बांसुरी वादकों के होठों पर यहीं की बांसुरी सजती है। मॉर्डन जमाने में इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बावजूद बांसुरी की डिमांड कम नहीं हुई है और उससे भी खास बात है कि इसे दुनियाभर तक पहुंचाने का काम आज भी पीलीभीत ही कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक खास तरह के बांस से ही बांसुरी बनाई जाती है, जो पीलीभीत में नहीं उगती, तो कहां से आता है ये बांस और कैसे तैयार होती है बांसुरी, आइए जानते हैं।

कई वैराइटी की बांसुरी है यहां मौजूद

पीलीभीत में ही देश की 90 प्रतिशत बांसुरी तैयार की जाती है। बेस्ट हैंडमेड बांसुरी के लिए देश-विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है पीलीभीत। सीधी फूंक वाली बांसुरी से लेकर बगल से फूंकने वाली हर तरह की बांसुरी का निर्माण यहीं होता है।

असम से आता है बांसुरी बनाने के लिए बांस

पीलीभीत बरेली मंडल का सबसे ज्यादा जंगल वाला इलाका है, लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी कि इन जंगलों में बांस नहीं पैदा होता। बांसुरी बिना गांठ वाले बांस से बनाई जाती है और यह बांस असम के सिल्चर शहर में उगता है और यहां से पीलीभीत पहुंचता है।

ऐसे बनाई जाती है बांसुरी

एक बांसुरी को बनाने में एक नहीं, बल्कि कई कारीगरों को लगना पड़ता है।

सबसे पहले बांस के बड़े टुकड़ों को बांसुरी के साइज के हिसाब से काटा जाता है।

काटने के बाद छीलने का प्रोसेस होता है।

फिर इन बांस के टुकड़ों में सुर भरने के लिए सलाखों को गर्म कर उसमें छेद किया जाता है।

इसके बाद बांसुरी के ऊपरी हिस्से में डॉट लगाकर सजाया जाता है।

तब जाकर बांसुरी तैयार होती है।

बांसुरी की कीमत

बांसुरी आपको 20 रुपए से लेकर 15,000 तक की मिल जाएगी। एक साथ बहुत ज्यादा लेने पर दाम कुछ कम हो जाता है, तो वहीं खास ऑर्डर पर कीमतें बढ़ भी जाती हैं।

मॉनसून में घूमने के साथ एडवेंचर भी करना है ट्राई, तो मध्य प्रदेश है इसके लिए बेहतरीन जगह

मानसून में पहाड़ों की प्लानिंग मुसीबत भरा डिसीजन साबित हो सकती है। ऐसे में घूमने के लिए डेस्टिनेशन के ऑप्शन्स न के बराबर रह जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये सही नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां घूमने का बेस्ट सीजन ही मानसून होता है। मध्य प्रदेश उन्हीं चुनिंदा जगहों में शामिल है।

नई दिल्ली। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में घूमने के शौकीनों के लिए काफी सारे ऑप्शन्स हैं। मानसून के दौरान घूमने के लिए मध्य प्रदेश सेफ जगह मानी जाती है। मध्य प्रदेश हर तरह क घुमक्कडों का स्वागत करता है। मतलब ये जगह नेचर लवर्स के लिए भी बेस्ट है और इतिहास प्रेमियों के लिए भी और एडवेंचर के लिए भी ठिकानों की कमी नहीं। बजट में आप इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

शिवपुरी

शांति और खूबसूरती से भरा है शिवपुरी। यहां का सुरवाया किला देखने लायक जगह है। जिसकी दीवारें और मंदिर के अवशेष प्राचीनकाल से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करने का काम करते हैं। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है, जहां घूमने का अनुभव बेशक यादगार रहेगा। नरवर किला की सैर आपको इतिहास से रूबरू होने का मौका देती है, तो बधैया कुंड जाकर सुकून के दो पल बिताना भी बहुत खास होता है।

दतिया

यहां पीताम्बरा पीठ मंदिर बेहद खास है। जो अपनी भव्य वास्तुकला और आध्यात्मिक अनुभव के लिए मशहूर है। यहां आकर बगलामुखी देवी का आशीर्वाद लेना न भूलें।

ओरछा

ओरछा की खूबसूरती का अंदाजा आपको यहां आकर ही लगेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान का आशीर्वाद तो लें ही, साथ ही यहां की नक्काशी को कैमरे में कैद करना न भूलें। बुंदेला राजाओं और उनकी परिवारों की याद में बने स्मारक और छतरियां यहां देखने लायक हैं। यहीं एकमात्र ऐसा मंदिर हैं, जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। ओरछा में वैसे पक्षी अभ्यारण्य भी है, जहां आप तरह-तरह के पक्षियों और पेड़-पौधों का दीदार कर सकते हैं।

मुरैना

पशु-पक्षियों को देखने का शौक रखते हैं, तो नेशनल चंबल सेंक्चुअरी जरूर आएं। जहां आप लुप्तप्राय घड़ियाल से लेकर लाल मुकुट वाला कछुआ देख सकते हैं। गंगा नदी में अठखेलियां करती हुईं डॉल्फिन्स को देखने का भी एक्सपीरियंस बड़ा ही मजेदार होता है। यहां पास में ही बटेश्वर मंदिर समूह भी है, जिसे विरासत का खजाना है।

लहसुन को छीलते वक्त दिमाग और टाइम दोनों होता है खराब, तो माइक्रोवेव से बनाएं इस काम को आसान

लहसुन कुकिंग का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है जिसकी थोड़ी सी मात्रा न सिर्फ डिश का जायका बढ़ाती है बल्कि उसके फायदे भी बढ़ा देती है क्योंकि लहसुन एंटी-बैक्टीरियल एंटी-फंगल और कई जरूरी विटामिन्स से भरपूर होता है लेकिन लहसुन को छीलना एक सिरदर्दी भरा काम होता है। हालांकि हल्का गर्म कर काफी हद तक इस काम को आसान बनाया जा सकता है।

नई दिल्ली। लहसुन का तड़का दाल से लेकर सब्जी तक के स्वाद में इजाफा कर देता है और नॉन वेजिटेरियन्स डिशेज का तो खास इंग्रेडिएंट ही लहसुन है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, लहसुन से खाने की खुशबू भी बढ़ जाती है, लेकिन लहसुन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके छीलना, जो एक टास्क से कम नहीं होता। हालांकि इस काम को आप बहुत ही आसानी से और जल्द निपटा सकते हैं उसे हल्का गर्म करके। आइए जानते हैं कैसे।

मास्टर शेफ सीजन- 1 की विनर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया पर लहसुन छीलने का ये आसान नुस्खा शेयर किया है। जो वाकई कमाल का है। इसकी मदद से आप इस बोरिंग काम को मजेदार बना सकते हैं और अपना काफी समय भी बचा सकते हैं।

लहसुन को छीलने का आसान उपाय

सबसे पहले लहसुन को ऊपरी सख्त भाग को काटकर अलग कर लें।

अब इसे Cling Wrap Sheet यानी टांसपेरेंट पन्नी में लपेट दें।

इसे माइक्रोवेव में 20 सेकंड तक गर्म कर लें।

माइक्रोवेव से निकालकर लहसुन की पूंछ पकड़कर इसे दबाएं, लहसुन आसानी से छिलके से निकल जाएंगे।

मिनटों में हो जाएगा लहसुन छीलने का काम।

टिप्स

अगर आपके घर में माइक्रोवेव न हो, तो आप इसे तवे या कड़ाही में हल्का भूनकर छील सकते हैं।

वैसे धूप में 20 से 30 मिनट रखने से भी काम बन जाएगा।

लहसुन को आसानी से छीलने के लिए उसे पांच से दस मिनट पहले पानी में भिगो दे। इससे भी छिलके आसानी से उतर जाते हैं।

ये भी पढ़ें:- गरमा-गर्म भात के साथ 'माछेर झोल' का साथ दोपहर Lunch के लिए है शानदार ऑप्शन

लहसुन के फायदे

लहसुन सेहत के लिए जरूरी कई सारे गुणों से भी भरपूर होता है। एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा लिए हुए लहसुन कई खतरनाक बीमारियों से हमें बचाता है। इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कई तरह के इन्फेक्शन्स से भी बचाव होता है।

सुबह या शाम, वेट लॉस के लिए किस समय वॉक करना है ज्यादा बेहतर?

तेजी से बदलती लाइफस्टाइल कई समस्याओं की वजह बन रही है। मोटापा इन्हीं समस्याओं में से एक है जिससे दुनियाभर में कई लोग परेशान हैं। ऑफिस में दिनभर बैठे रहने की वजह से अक्सर वजन बढ़ने लगता है जो कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। ऐसे में वॉक वजन कंट्रोल करने का एक बढ़िया तरीका है। आइए जानते हैं सुबह या शाम कब वॉक करना ज्यादा बेहतर होता है।

नई दिल्ली। बदलती लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल की वजह से लोग इन दिनों कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। दिनभर ऑफिस स्क्रीन के सामने बैठे रहने की वजह से इन दिनों लोग मोटापे का शिकार होने लगे हैं। कम उम्र में ही आजकल कई लोग बाहर निकलती तोंद से परेशान हैं। मोटापा कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। ऐसे में हेल्दी और फिट रहने के लिए अपने वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इन दिनों लोग डाइटिंग के साथ-साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देने लगे हैं। हालांकि, बिजी शेड्यूल की वजह से प्रॉपर वर्कआउट करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसलिए ज्यादातर लोग वॉकिंग का विकल्प चुनते हैं।

यह एक्सरसाइज का एक आसान तरीका है, जिसे लोग सुबह या शाम अपनी सुविधा के मुताबिक करना पसंद करते हैं। वॉकिंग वजन घटाने और अपने मूड को बेहतर बनाने का एक मजेदार और आसान तरीका है। चलते समय हम जब भी कदम उठाते हैं, तो इससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। हालांकि, लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर वॉक करने का सही समय क्या है। अगर आप भी अक्सर इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वेट लॉस के सुबह या शाम कब वॉक करना बेहतर होता है।

मॉर्निंग वॉक के फायदे

सुबह के समय वॉक करना कई मायनों में हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सुबह का पॉजिटिव माहौल और ताजी हवा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। साथ ही इससे हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के अन्य फायदे निम्न हैं-

सुबह के समय वॉक करने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है।

सुबह वॉक करने से आपके नींद के पैटर्न में सुधार होता है, जिससे रात में सुकून की नींद आती है।

इससे आपके मूड और एनर्जी लेवल में भी सुधार होता है, जिससे आपका दिन प्रोडक्टिव हो जाता है।

ताजी हवा और सुबह की नेचुरल रोशनी आपके शरीर और दिमाग को एनर्जेटिक बना सकते हैं, जिससे आप पूरे दिन पॉजिटिव फील करते हैं।

सुबह के समय वॉक करने से आप सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं, जिससे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जो आपकी हड्डी और इम्युनिटी के लिए जरूरी है।

शाम के वॉक करने के फायदे

शाम के समय वॉक करने के भी अपने कई फायदे हैं। दिन भर के काम या अन्य गतिविधियों के बाद, शाम की सैर आराम और तनाव दूर करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इसके अलावा इससे अन्य कई फायदे मिलते हैं, जो निम्न हैं-

शाम के समय टहलने से दिन भर के तनाव को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

शाम को सैर करने से पाचन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है और आप लेट नाइट स्नैकिंग से बचे रहते हैं।

रात के खाने के बाद वॉक करने से आपके शरीर को खाना प्रोसेस करने में मदद मिलती है और सोने से पहले अनहेल्दी स्नैक्स खाने की क्रेविंग कम हो सकती है।

सुबह या शाम- वेट लॉस के लिए कब करें वॉक

सुबह और शाम दोनों की समय वॉक करने से वजन घटाने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें से ज्यादा प्रभावी क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौनसा समय आपके रूटीन के मुताबिक फिट बैठता है और आपका शरीर किस समय कैसे प्रतिक्रिया करता है। ऐसे में वॉक करने के लिए ऐसा समय चुनें, जो आपके शेड्यूल, एनर्जी लेवल और लाइफस्टाइल के अनुरूप हो।

अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं, जो सुबह की वॉक आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित होगी। वहीं, अगर आप दिन ढलने के बाद एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं, तो शाम के समय वॉकिंग के साथ अपने दिन को खत्म कर सकते हैं।

कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार स्टूडेंट्स की सुरक्षा की ताक पर रख गया उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-मंत्री गोपाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए केजरीवाल सरकार क़ानून बनाएगी। इस बाबत बुधवार की दिल्ली सचिवालय में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यूपीएससी अभ्यर्थियों के साथ चर्चा की गई और उनके सुझाव लिए गए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, मेयर शैली ओबरॉय, चीफ व्हिप दिलीप पांडेय सहित दिल्ली सरकार और एमसीडी के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

आज बैठक में छात्रों के साथ उनकी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। छात्रों ने कोचिंग इंस्टिट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों, नियमों की अनदेखी, बढ़ी फ़ीस वसूली सहित मनमाना किराए आदि विषयों से संबंधित अपनी समस्याएँ साझा की। छात्रों ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे में ज़िम्मेदार लोगों पर सख़्त एक्शन लेने की माँग की। साथ ही छात्रों ने कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार द्वारा प्रस्तावित क़ानून को लेकर भी अपने सुझाव रखे।

इस मौक़े पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार छात्रों की बेहतरी और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम इनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा और बेहतरी के लिए हम संभव प्रयास करेंगे।

बता दे कि, बैठक में छात्रों ने कोचिंग इंस्टिट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ी हुई फ़ीस के अलावा स्टूडेंट्स किराए के घरों में मनमाना किराया देने के बावजूद कई बार बुनियादी सुविधाएँ न मिलने तक का मुद्दा उठाया। साथ ही बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज के सील होने के कारण पढ़ाई में आ रही बाधाओं का मुद्दा भी उठाया।

इसपर सभी मंत्रियों और मेयर ने छात्रों को जल्द से जल्द उनके शोर्ट टर्म और लॉंग टर्म समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, कोचिंग संस्थानों को लेकर क़ानून बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्टूडेंट्स की राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम उसके अनुरूप क़ानून बना सके।

कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि, कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार स्टूडेंट्स की सुरक्षा की ताक पर रख गया उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कदम उठायेंगे जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो। मेयर शैली ओबरॉय ने भी कहा कि, हमारा छात्रों को वादा है, जो कोचिंग संस्थान नियमों की धज्जियाँ उड़ाते है, उनपर सख़्त कारवाई की जाएगी। हमारे लिए छात्र महत्वपूर्ण है, और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

कोचिंग इंस्टिट्यूट रेगुलेट पर लाएगें कानून: आतिशी

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा है कि बेलगाम कोचिंग इंस्टिट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, इस मामले में स्टूडेंट्स से भी सुझाव लिए जाएगे। ओल्ड राजेन्द्र नगर के राव कोचिंग इंस्टिट्यूट में हुए हादसे में तीन स्टूडेंट्स की मौत के बाद केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है।दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टिट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिए जाएगे। दूसरी ओर एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थान पर कारवाई के आदेश दिए गए है। इनमें ओल्ड

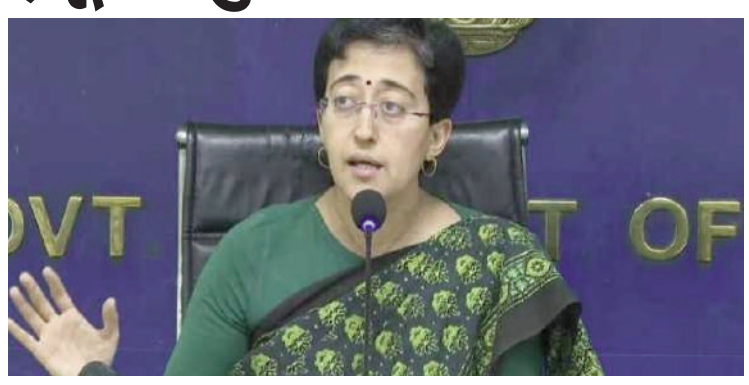

राजेन्द्र नगर,मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, और लक्ष्मी नगर में अब तक 30 बेसमेंट सील किए गए है।कई कोचिंग सेंटरों को शो कॉश नोटिस भी जारी किया है।पूरी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेगें। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को बारिश के बाद पानी भरने से हादसा हो गया। इस दौरान कोचिंग सेंटर में पढने वाले 3 स्टूडेंट्स की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी।इस मामले में पुलिस ने हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर कई टीमें गठित की है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के संचालक अभिषेक गुप्ता और को ऑरडिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मे सिर्फ 2-3 मिनट में ही 12 फीट तक पानी भर गया था। उस पानी में तीन स्टूडेंट्स दो लडकी और एक लडके की डूबने से मौत हो गई। इस बावत आम लोगों का आरोप है कि कुछ दिनो बाद मामला फिर ठंडा पड जाएगा। इससे पहले विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में भी सिलिंडर फटने से 7 शिशुओ की मौत हो गई थी। इससे पहले मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 स्टूडेंट्स घायल हो गए थे। बावजूद इसके एमसीडी, डीडीए, और पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते इस घटना ने आम आदमी समेत कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। बुद्धवार को हाईकोर्ट ने भी एमसीडी, समेत पुलिस को तबीयत से फटकार लगाई है। कोर्ट इस मामले में गुरूवार को सुनवाई जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाने की घोषणा सिर्फ छात्रों को गुमराह करना वाला: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नईदिल्ली। राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूब कर मरने वाले छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में सभी 280 ब्लाक कांग्रेस कमेटी में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में क्षेत्रीय छात्रों, रिहायशी लोगों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सहित ब्लाक, जिला, अग्रिम संगठन, सेल एवं विभागों के पदाधिकारी सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव बादली विधानसभा के ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र और दिल्ली में सत्तासीन भाजपा व आम आदमी पार्टी छात्रों को न्याय दिलाने की जगह उनकी मौत पर खुली राजनीति कर रहीं है। जांच के नाम पर केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय ने अधिकारियों की कमेटी गठित करके और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा करके सिर्फ मामले को दबाने के लिए लीपापोती की है और दिल्ली पुलिस ने इनसे भी आगे बढ़कर थार गाड़ी चालक को अरेस्ट करके दोष उस पर मढ़ने की स्क्रिप्ट तैयार ली है, क्या बारिश में गाड़ी चलाने वालों को भी दिल्ली पुलिस दोषी साबित करेगी?

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी का छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देना कि दोषियों को सजा दिलवाऐंगे, पूरी तरह भ्रमित करने वाला है। यादव ने पूछा कि जब दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनो पर आम आदमी पार्टी सत्तासीन है, फिर दोषी किसे बनाऐंगे और सजा किसे दिलाऐगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को निरस्त कर ओर छोटे ठेकेदारों पर कार्यवाही करके आम आदमी पार्टी छात्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाने की कवायद तो नही?

उन्होंने कहा कि डीएम की जांच की अंतरिम रिपोर्ट में घटना से जुड़े वही तथ्य है जो मीडिया में उपलब्ध रहे। रिपोर्ट में घटना से जुड़ी जानकारियों को समयबद्ध तरीके से नहीं रखा है और घटना घटने के बाद विभागों ने सूचना के बावजूद तुरंत आवश्यक कदम नहीं उठाए और मंत्री आज तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, यह अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है दिल्ली नगर निगम ने मुख्य सचिव को सौंपी गई रिपोर्ट में अपने अलावा सभी को दोषी साबित कर रही है जबकि जिस नाले के टूटने से बेसमेंट में पानी भरा उसे साफ करना दिल्ली नगर निगम के आधीन आता है।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजेन्द्र नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार दिल्ली की कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाने की घोषणा सिर्फ छात्रों को गुमराह करने के लिए है क्योंकि वर्ष 2020 में सूरत कांड के बाद आननफानन में एक रेगुलेशन बनाने की घोषणा की थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की समस्याओं का समधान निकलाने की बजाय सुझाव मांगकर इसे भी इवेंट बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि उच्च पदों की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए केजरीवाल सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट व पी.जी. के लिए स्थाई सुरक्षा गाईडलाईंस लाए और मास्टर प्लान 2041 के प्रस्ताव अनुसार कोचिंग सेन्टर एवं पीजी स्थाई रेगुलेशन एक्ट बनाने पर काम करे।

उन्होंने कहा कि राउ इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी वर्ष 2021 के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर जुलाई 2024 में फायर एनओसी करोल बाग जोन को बिल्डिंग की कमियों से जुड़ी सभी जानकारी होने के बावजूद दिया गया और दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में बिल्डिंग बायलॉज़ का उलंघन कर चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कोई कार्यवाही हुई। इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में वर्ष 2023 में हुई घटना तथा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाबजूद दिल्ली नगर निगम ने कोई

हाईकोर्ट ने छात्रों की मौत पर एमसीडी समेत पुलिस को लगाई फटकार ,कहा मुफ्तखोरी संस्कृति पर भी फैंसला करना होगा

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को भरे बरसात के 12 फीट पानी में डूबने से हुई तीन छात्रों की मौत मामले पर दिल्ली हाइकोर्ट भडक गया और एमसीडी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी जबरदस्त फटकार लगाई और कहा, मुफ्तखोरी संस्कृति पर भी फैंसला करना होगा।

अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए एमसीडी कमिश्नर, जिले के डीसीपी और जांच अधिकारी (IO) को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की कारवाई पर हैरानी जताई। अदालत ने कहा कि अजीब जांच चल रही है, पुलिस पास से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है,लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अदालत ने जवाब तलब किया कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने

अभी तक क्या किया है? पुलिस ने इंस्टिट्यूट के सामने से पानी में निकलने वाले कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन

एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए है? दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से बाकायदा हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा है।बता दें कि अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में पक्षकार बनाया और कहा कि जांच अधिकारी को गुरूवार 1 जुलाई को सभी फाइलें कोर्ट में लेकर आने को कहा है। इसके अलावा एमसीडी कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया गया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कल हम इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए आदेश पारित करेगे। अदालत ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करार दिया है। और सख्ती के साथ कहा कि दुर्भाग्य से बहुत से अधिकारी परस्पर विरोधी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं।बहुत ज्यादा दोषारोपण हो रहा है।दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कभी-कभी सीनियर अधिकारियों को भी आना पडता है।और स्वीकार करना पडता है कि जो अपने एसी वाले आफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आप सोचते है कि इमारतों के जरिए आप प्राकृति से लड सकते है तो आप गलत है। और ये कैसी योजना है ? एक दिन आप सूखे की शिकायत करते है और अगले दिन बाढ आ जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपको इस मुफ्तखोरी संस्कृति पर फैसला करना होगा। अदालत ने फटकारा कि आप बहुमंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे है, लेकिन कोई उचित नाली नहीं है।आपने सीवेज को स्टार्म वाटर ड्रेन के साथ मिला दिया है, जिससे पानी का बहाव उल्टा हो जाता है। आपकी सिविक ऑथोरिटी दिवालिया हो चुकी है। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप बुनियादी ढांचे कैसे उन्नत करेगे? आप मुफ्तखोरी संस्कृति चाहते है। आप कोई पैसा इक्ट्ठा नहीं कर रहे है, इसलिए आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम एमसीडी से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहते है।वे कहते है कि 5 करोड से ज्यादा की कोई भी परियोजना स्थायी समिति से मंजूरी लेगी। लेकिन अब तक स्थायी समिति नही है।कोर्ट ने कहा कि इस शहर को कैसे चलाने की योजना बना रहे है? जब आप 5 करोड से अधिक की राशि मंजूर नहीं कर सकते ? अदालत ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस कहां है? कौन जांच कर रहा है? वहां इतना पानी कैसे जमा हो गया?

दिल्ली मेट्रो में चली हवाई चप्पल और थप्पड़, दो लोगों में हुए कलेश का वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो में अक्सर मारपीट या डांस के वीडियो वायरल होते हैं। लोग इन्हें जमकर शेयर करते हैं और आनंद भी लेते हैं। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दूसरे को चप्पल से मार रहा है। वहीं दूसरे भी उसके साथ मारपीट करता है। लोग वीडियो में तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। ज्यादातर मेट्रो के अंदर या स्टेशन के कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन पर लोग चर्चा करना नहीं भूलते। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल साइट एक्स पर वायरल होते एक वीडियो में एक शख्स चप्पल मार रहा है। उसके बाद दूसरे शख्स भी उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। फिर वह उसके पास से दूर चला जाता है। जब चप्पल मारने वाला उसके पीछे भागता है तो एक यात्री उसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शांत हो जाती है।

इसके बाद दूसरा शख्स भी उसको मारने लगता है। दोनों में मारपीट होने लगती है। वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है।

लोगों ने किए तरह-तरह के कमेंट

अब यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और चर्चा में आ गया है। लोग वीडियो पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक शख्स ने कमेंट किया, दिल्ली मेट्रो में दुनिया की किसी भी मेट्रो के मुकाबले सबसे ज्यादा शांत यात्री हैं। हर दिन मुफ्त मनोरंजन और रियलिटी शो का प्रसारण। दिल्ली मेट्रो को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ यात्री ही हारते हैं।

एक एक्स यूजर ने लिखा, भाई ये सिक्योरिटी गार्ड एक्शन नहीं लेते। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, दिल्ली मेट्रो और लफड़ा की कभी न खत्म होने वाली प्रेम कहानी।

'यह हमारी विफलता, अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था', ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर एमसीडी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे ने देशभर को झकझोर दिया। कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना ने प्रशासनिक, नगर निगम की लापरवाही उजागर कर दी, जिनकी वजह से कोचिंग सेंटरों में छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को घटना को लेकर उसकी तरफ से हुई विफलता को स्वीकार किया है।

एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने बुधवार को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत में नगर निकाय की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हादसे से पता चलता है कि भवन निर्माण को लेकर कई गंभीर संरचनात्मक मुद्दे हैं, जिन्हें सामने लाने की आवश्यकता है।

एजेंसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए

ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स से बातचीत करते हुए वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी ने कहा कि इस घटना के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, एजेंसी को अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था।

छात्रों से की मुलाकात

तारिक थॉमस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि जैसा आपने कहा, हमारे पास कई संरचनात्मक मुद्दे हैं। इन्हें व्यवस्थित तरीके से सुधारने की आवश्यकता है। यही मेरा समाधान है।

'मैं स्वीकार करता हूं, यह हमारी विफलता है'

एक छात्र की शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि यह हम सबकी और व्यक्तिगत रूप से मेरी विफलता है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि यह नहीं है, यह अधिकारियों के रूप में हमारी विफलता है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

एक छात्र ने पूछा कि इस घटना में प्रशासन के प्रदर्शन का मूल्यांकन किन मापदंडों पर किया जाना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, इसे समझने दीजिए। घटना में जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वीकार करता हूं कि हमें अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई बहाना नहीं है।

उन्होंने कहा कि इमारत, भवन निर्माण में संरचनात्मक मुद्दे गंभीर हैं। इन पर कारने की आवश्यकता है. दिल्ली में विकास इतना तेज रहा है कि यह मास्टल प्लान से दूर था।

इस तरह गई तीनों छात्रों की जान

ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम सात बजे लगभग बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें अनुमति सिर्फ स्टोर चलाने की थी। शनिवार को भारी बारिश की वजह इमारत में शीशे का गेट टूटने के कारण बेसमेंट में पानी चला गया। गेट को नुकसान एक थार चालक की वजह से पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

बेसमेंट में 35 छात्र पढ़ रहे थे, इस दौरान तीन छात्रों को छोड़कर सभी बाहर आ गए। बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमैट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाने से बिजली भी चली गई। बिजली जाने की वजह से दरवाजे नहीं खुले और हादसे में दो छात्रा व एक छात्र अंदर फंसे रह गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

बारिश ने लोगों को दी उमस से राहत, अगले दो-तीन दिन ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार

दिल्ली में वर्षा के यलो अलर्ट के बावजूद उमस भरी गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ाया। वहीं बुधवार देर शाम हुई बारिश से आमजन को राहत मिली है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2012 के बाद पहली बार 39 डिग्री पार पारा पहुंचा। अगले दो-तीन दिन बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को एक बार फिर मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित होने के बाद आज देर शाम जोरदार बारिश हुई। इससे पहले हल्की से मध्यम वर्षा के कारण यलो अलर्ट में दिनभर तेज धूप निकली रही। उमस से लोगों का हाल बेहाल रहा तो जुलाई माह के आखिरी हफ्ते में अधिकतम तापमान नया रिकॉर्ड बनाते हुए 39 डिग्री पार चला गया।

अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बुधवार से अगले तीन दिनों तक दिल्ली में अच्छी वर्षा हो सकती है। ऐसी संभावना जताई थी। इसी कारण बुधवार के लिए आरेंज जबकि उसके बाद अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

IMD ने बादल छाए रहने की जताई थी संभावना

मौसम विभाग (IMD Alert) का पूर्वानुमान था कि बुधवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा एवं कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि बादल तो छाए नहीं रहे लेकिन बारिश जरूर हुई।

तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड

मंगलवार को सुबह से ही धूप निकल गई थी, दिन चढ़ने के साथ- साथ यह और तीखी होती गई। इससे उमस भी बढ़ी और तापमान में भी इजाफा देखने को मिला। अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 39.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

डाक कांवड़ ले जा रहे तीन कांवड़ियों को ट्रक ने कुचला, एक की मौत; दो घायल

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम से एद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर डाक कांवड़ लेकर जा रहे तीन लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। घटना में एक की मौत हो गई। जबकि दो कांवड़िये घायल हो गए। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर राजस्थान के बालेश्वर धाम जा रहा था। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में रामपुरा फ्लाइओवर के पास सुबह चार बजे दुर्घटना हुआ।

गुरुग्राम। हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर राजस्थान के बालेश्वर धाम जा रहे तीन कांवड़ियों को खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के रामपुरा फ्लाइओवर के पास पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने कुचल दिया। इस हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जब दो गंभीर रूप से घायल हैं।

हादसे के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार

हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। खेड़कीदौला थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

ट्रक ने कांवड़ियों की बाइक को मारी टक्कर

राजस्थान का कांवड़ियों का एक जत्था डांक कांवड़ लेकर हरिद्वार से वापस जा रहा था। बुधवार सुबह चार बजे खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के रामपुरा फ्लाइओवर के पास जब जत्थे के लोग पहुंचे, इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों की बाइक में टक्कर मार दी।

इस पर कांवड़िये अभिषेक मीना, हेमंत मीना और योगेश सवार थे। गंभीर रूप से घायल तीनों को अस्पताल ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू

कांवड़ियों के मुताबिक ट्रक मिट्टी से भरा था और ओवरलोड था। उन्होंने चालक के नशे में होने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। थाना पुलिस (Gurugram ने समझाकर लोगों को हाईवे से हटाया और मामले की जांच शुरू कर दी।

मणिपाल अस्पताल के तीन चिकित्सकों के खिलाफ केस दर्ज, ऑपरेशन थियेटर में हुई थी युवती की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

मणिपाल हॉस्पिटल में उपचार के दौरान युवती की मौत के मामले में तीन चिकित्सकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि युवती की रीढ़ की हड्डी में शिकायत बताकर भर्ती कराया गया था। इसके बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की जिससे युवती की मौत हो गई।

गाजियाबाद। मणिपाल अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत पर उसके पिता ने अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि अस्पताल में गलत ऑपरेशन के कारण उनकी पुत्री की मौत हुई है।

प्रिया की रीढ़ की हड्डी में बताई थी परेशानी

विश्वास नगर में रहने वाले राजवीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी प्रिया वर्मा 18 अक्टूबर को मामूली परेशानी होने पर उपचार के एनएच- नौ पर लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक सोसायटी के पास स्थित मणिपाल अस्पताल गई। वहां न्यूरोसर्जन डॉ. गजेंद्र सिंह सिंधू ने धन उगाही के उद्देश्य से प्रिया की रीढ़ की हड्डी में परेशानी बताई।

अक्टूबर 2023 का है मामला

इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन के लिए उसको अस्पताल में भर्ती किया और गलत दवाएं देने और ऑपरेशन में लापरवाही के कारण प्रिया की तबीयत बिगड़ गई और ऑपरेशन थियेटर में ही उसकी मृत्यु हो गई।

तीन चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट

आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉ. गजेंद्र सिंह सिंधू, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. पवन कुमार व उनकी टीम ने लापरवाही की। जिनके पास अनुभव की कमी है। तीनों चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

नोएडावासियों के लिए खुशखबरी, नवरात्रि में आएगी यीडा की एक और आवासीय भूखंड योजना

YEIDA Plot Scheme

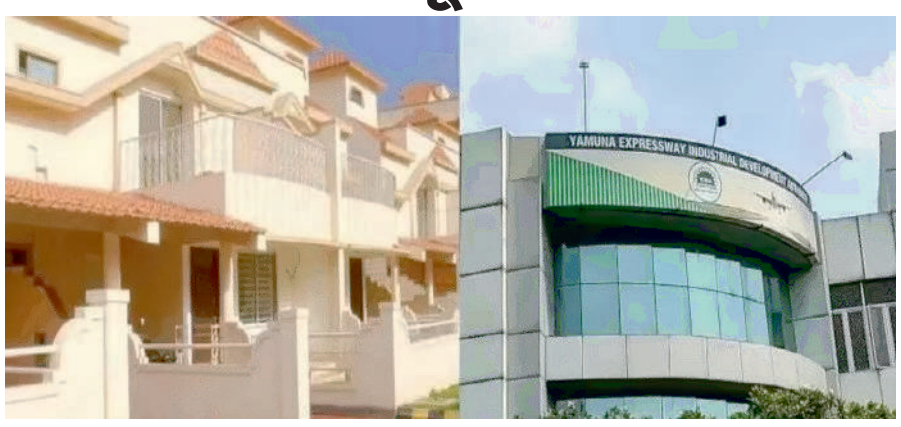

यमुना प्राधिकरण ने नोएडा में आवासीय प्लॉट योजना शुरू किया हुआ है। कहा जा रहा है कि अब वह नवरात्रि में एक और आवासीय भूखंड योजना लाने जा रहा है। बता दें यीडा ने पांच जुलाई को आवासीय भूखंड की योजना थी। इस योजना में 361 भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मदाबाद खेड़ा में भी तकरीबन सात सौ भूखंड के लिए जमीन उपलब्ध की गई है।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण नवरात्रि में एक और आवासीय भूखंड योजना निकालेगा। इस योजना में तकरीबन 2500 भूखंड शामिल होंगे। खासबात यह है कि प्राधिकरण इस योजना में 120 वर्गमीटर से छोटे भूखंड भी आवंटित करेगा।

यमुना प्राधिकरण ने पांच जुलाई को आवासीय भूखंड की योजना निकाली है। इस योजना में 361 भूखंड शामिल हैं। योजना में 120 वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंड शामिल किए गए हैं।

भट्टा पारसौल गांव में करीब 975 भूखंड के लिए जमीन उपलब्ध

लेकिन प्राधिकरण इसी वित्त वर्ष में एक और आवासीय भूखंड योजना निकालने की तैयारी कर रहा है। यह योजना नवरात्रि के दौरान लाई जाएगी। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण को भट्टा पारसौल गांव में करीब 975 भूखंड के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है।

यह जमीन पूर्व में सेक्टर 18 में 2009 की योजना के अंतर्गत आवंटित भूखंडों के लिए थी, लेकिन जमीनी विवाद के कारण इस जमीन पर प्रस्तावित भूखंडों के आवंटियों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया।

करीब सात सौ भूखंड के लिए जमीन हुई उपलब्ध

इसके अतिरिक्त मोहम्मदाबाद खेड़ा में भी तकरीबन सात सौ भूखंड के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। 120 वर्गमीटर से छोटे भूखंड योजना में शामिल करने पर इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। योजना के लिए करीब 2500 भूखंड उपलब्ध होंगे।

अधिक से अधिक लोगों से प्राधिकरण क्षेत्र में अपना घर बनाने का मौका देने के लिए 90 वर्गमीटर के छोटे भूखंड की योजना में शामिल किए जाएंगे। सीईओ ने योजना निकालने से पहले सेक्टर में आंतरिक विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम ग्रिड योजना: ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की तैयारी में जुटा निगम

परिवहन विशेष न्यूज

सीएम ग्रिड योजना के तहत गाजियाबाद जिले में नगर निगम दूसरे चरण में ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना पर करीब 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। सभी सड़कों को बनाने से पहले ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। लोगों के बैठने के अलावा पार्किंग और फुटपाथ भी बनाए जायेंगे। जो काफी आकर्षक होंगे।

गाजियाबाद। सीएम ग्रिड योजना के तहत दूसरे चरण में नगर निगम ने ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चिह्नित कर लिया गया है। सीएम ग्रिड योजना के लिए सड़कों का चयन करने वाली स्थानीय कमेटी ने इस पर फाइनल मुहर लगा दी है। इस पर करीब 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं।

वैशाली सेक्टर-चार शॉपिक्स मॉल के पास दो सड़क चिन्हित

निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि डाबर तिराहे से कौशांबी बस अड्डे को जाने वाले मार्ग के साथ कौशांबी होते हुए ईडीएम माल के पास गाजीपुर बॉर्डर पर निकलने वाली सड़क के साथ वैशाली सेक्टर-चार शॉपिक्स मॉल के सामने वाली सड़क और वैशाली से रामप्रस्था ग्रीन सोसायटी की तरफ वाली वाली दो सड़कों को चिह्नित किया गया है।

इसके अलावा इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड, गौड ग्रीन एवेन्य को जाने वाली सड़क, ज्ञानखंड और न्यायखंड के बीच से अभिखंड होते हुए साईं मंदिर को जाने वाल सड़क।

साथ ही काला पत्थर रोड से सीआईएसएफ की तरफ जाने वाली दो सड़कों को सीएम ग्रिड योजना के तहत दूसरे चरण में विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाकर लगवाई जाएंगी लाइटें

इन सभी सड़कों का ड्रोन सर्वे भी कराया जा चुका है। इन सड़कों पर लगे बिजली के खंभों व सड़क के ऊपर से गुजर रहे तारों को हटवाकर अंडग्राउंड कराया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाकर लाइटें लगवाई जाएंगी, जिससे फुटपाथ काफी आकर्षक होगा।

लोगों के बैठने के लिए कुछ-कुछ दूरी पर बैंच व गजिबो हट बनवाई जाएंगी। इसके अलावा वाहनों के खड़े करने के लिए पार्किंग व चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि प्रोजेक्ट की डीपीआर शासन में स्वीकृति के भेजी जाएगी।

वहां उच्चाधिकारी की कमेटी तकनीकी रूप से चेक करने के साथ सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों के चिह्कांन के लिए तय मानकों को देखेगी। इसके बाद स्वीकृति मिलेगी। शासन की स्वीकृति मिलते ही जिन सड़कों का चयन योजना के तहत होगा।

उन पर काम शुरू कराया जाएगा। मालूम हो कि सीएम ग्रिड योजना के तहत दो सड़कों के सुंदरीकरण के लिए टेंडर लगा हुआ है। छह अगस्त को टेंडर खोले जाएंगे। इसके बाद वर्कऑर्डर जारी कर काम शुरू कराया जाएगा।

जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद की रोकथाम के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

डॉ. सौरभ मालवीय

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नया विधेयक प्रस्तुत किया, जो मंगलवार को पारित हो गया। इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 नाम दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जनहित में बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नए विधेयक को पारित करवाकर एक और इतिहास रच दिया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से वे भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है तथा वह इसी का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं।

विगत दीर्घ काल से लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं। प्रकरणों के अनुसार प्रेम प्रसंग में पड़कर लड़कियां दूसरे धर्म के पुरुषों से विवाह कर लेती हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात् इन लड़कियों पर ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत सी लड़कियां ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने पर विवश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। जो लड़कियां ऐसा नहीं करतीं, उनका जीवन नारकीय बन जाता है। उन्हें ससुराल में यातना एवं अपमान का सामना करना पड़ता है।

अनेक प्रकरणों में पति अथवा ससुराल पक्ष द्वारा लड़कियों को बेच देने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। ऐसे प्रकरणों में लड़कियों की हत्याओं के मामले भी प्रकाश में आए हैं। निःसंदेह ऐसे प्रकरण किसी भी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

अब उत्तर प्रदेश में नया कानून बनने से कुछ संतोषजनक होने की आशा जगी है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद की रोकथाम के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नया विधेयक प्रस्तुत किया, जो मंगलवार को पारित हो गया। इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 नाम दिया गया है। इस नए विधेयक के अनुसार नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने तथा उसे बेचने पर आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार सामूहिक रूप से जबरन धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान है।

ऐसे प्रकरण भी सामने आते रहते हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से भारी मात्रा में धनराशि आती है। योगी सरकार की दूरदर्शिता के कारण अब इस पर भी रोकथाम लग सकेगी। इस विधेयक में विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए आने वाले धन पर भी अंकुश लगाने हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं। विदेशी अथवा अपंजीकृत संस्थाओं से धन प्राप्त करने पर 14 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन अथवा उसकी धन-संपत्ति को भय अथवा हानि में डालता है, उस पर बल प्रयोग करता है, उसे विवाह का झांसा देता है, लालच देकर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बेचता है, तो उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। दोषी को पीड़ित के उपचार एवं पुनर्वास के लिए भी आर्थिक दंड चुकाना होगा। अब जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। इससे पूर्व केवल पीड़ति व्यक्ति, उसके परिवारजन अथवा संबंधी ही प्राथमिकी दर्ज करवा सकते थे।

इस प्रकार योगी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने की दिशा में प्रथम पग उठा लिया है। अब इस विधेयक को विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद भेजा जाएगा। तत्पश्चात इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके पश्चात इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व नवंबर 2020 में योगी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। इसके पश्चात फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 अस्तित्व में आया था। इस विधेयक के अंतर्गत दोषी को एक से 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था। इस विधेयक के अंतर्गत केवल विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन ही अमान्य था। किसी से झूठ बोलकर अथवा उसे धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया था। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे दो माह पूर्व मजिस्ट्रेट को सूचित करने का प्रावधान था। विधेयक के अनुसार जबरन अथवा धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपए आर्थिक दंड के साथ एक से डेढ़ वर्ष के कारावास का प्रावधान था। यदि दलित लड़की का धर्म परिवर्तन होता है तो 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड के साथ तीन से 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान था।

उल्लेखनीय है कि जबरन धर्मांतरण के दृष्टिगत देश के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू हैं। इनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा सम्मिलित हैं। महारष्ट्र में भी जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विधेयक लाने की बात कही जाती रही है, किंतु इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है।

पूर्व के कानून की तुलना में नए कानून को अधिक सशक्त एवं कठोर बनाया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लव जिहाद के प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिन्दुत्ववादी संगठन लम्बे समय से कठोर कानून की मांग करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि कठोर कानून से ही उनकी बहन-बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो लव जिहाद को 'मिथ्या' की संज्ञा देता है। इस वर्ग का कहना है कि देश में 'लव जिहाद' नाम की कोई चीज नहीं है। प्रश्न यह भी है कि यदि ऐसा है तो फिर यही वर्ग इस प्रकार के कानूनों की आलोचना क्यों करता है?

वास्तव में यह विधेयक किसी समुदाय या वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं है, अपितु यह केवल जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है- ₹कानून में जो संशोधन और सुधार हो रहा है उसके पीछे यह मकसद है कि और कड़ाई से नियम लागू हों और इस तरह की चीजें न हो। विपक्ष जो कह रहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यह कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, वे इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे और उन्हें वोट देता रहे, वे सरकार बनाते रहें और मुसलमानों को धोखा देते रहें।"

कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम धर्म नहीं देखता है। यदि प्रेम की बात की जाए, तो प्रेम त्याग का दूसरा रूप है। प्रेम की बात करने वाले लोगों को त्याग के नाम पर सांप सूंघ जाता है। यह कैसा प्रेम है, जो केवल लड़की से उसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान छीन लेता है। यदि पुरुष इतना ही प्रेम करने वाला है, तो वह लड़की का धर्म स्वीकार क्यों नहीं करता? यह कैसा एक पक्षीय प्रेम है?

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

सरकारी नीतियों से चालू वित्त वर्ष में ई-बस की बिक्री में हो सकती है 80 प्रतिशत की बढ़त

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार, 30 जुलाई को आईएएनएस की खबरों के अनुसार, सरकारी नीतियों के समर्थन के कारण चालू वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री साल-दर-साल 75-80% बढ़कर 6,000-6,500 तक पहुंचने की उम्मीद है।

रिसर्च फर्म क्रिसिल रेटिंग्स की ओर से कहा गया कि राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) की ओर से ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत ट्रेडर्स के जरिए ई-बस के बड़ी संख्या में ऑर्डर दिए जाने के कारण चालू वित्त वर्ष में इनकी बिक्री 75 से 80 प्रतिशत बढ़कर 6,000 से लेकर 6,500 यूनिट्स तक पहुंच सकती है। इन स्कीमों में फेम (1 और 2), पीएम ई-बस सेवा स्कीम और नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (एनईबीपी) शामिल है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सरकार की ओर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम उत्सर्जन पर जोर दिया जा रहा है। इसके कारण ई-बस को तेजी से अपनाया जा रहा है।

क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर गौतम शाही ने कहा कि ई-बस को तेजी से अपनाया जा रहा है, क्योंकि जीसीसी मॉडल के तहत एसटीयू और बस ऑपरेटर्स के हितों का ध्यान रखा गया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि ई-बस ऑर्डर में बढ़त होने से उत्पादन सस्ता हो जाएगा। साथ ही बैटरी की कीमत में भी कमी आएगी। इससे ई-बस की कीमत कम होगी। जिससे सीधा फायदा एसटीयू और बस ऑपरेटर को होगा। लागत कम होने के चलते ई-बस के चलन में भी इजाफा होगा।

क्रिसिल रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर पल्लवी सिंह ने कहा कि मौजूदा मजबूत ई-बस ऑर्डरबुक, साथ ही पीएम ई-बस सेवा योजना-4 के तहत दिए जाने वाले 7,800 बसों के बचे ऑर्डर से इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी उम्मीद है कि सरकार की ओर से इस स्कीम को बढ़ाया जाएगा। इससे चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में ई-बस की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

केईआरसी ने इमारतों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नए मानदंड पेश किए

परिवहन विशेष न्यूज

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने अपने नवीनतम स्वप्रेरणा आदेश में राज्य के शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक/आवासीय इमारतों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राज्य विद्युत विनियामक ने कहा कि इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता लाकर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। केईआरसी ने कहा कि उसे हाउसिंग सोसायटियों से उनके परिसर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में आने वाली बाधाओं के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर केईआरसी के नए दिशा-निर्देशों में ऐसी इकाइयों को या तो सामान्य सुविधाओं के लिए या व्यक्तिगत ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थापित करने का आह्वान किया गया है। मानदंड पूरे परिदृश्य में स्थानीय डिस्कॉम भूमि के बारे में भी बात करते हैं। नए मानदंडों में हाइलाइट किए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

केईआरसी ने अपने आदेश में कहा कि 2024 के टैरिफ ऑर्डर के अनुसार, एलटी 6(सी) के तहत ईवी टैरिफ 4.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्थानीय डिस्कॉम उपभोक्ताओं, प्रमोटरों, अधिभोगियों, मालिकों और वाणिज्यिक और

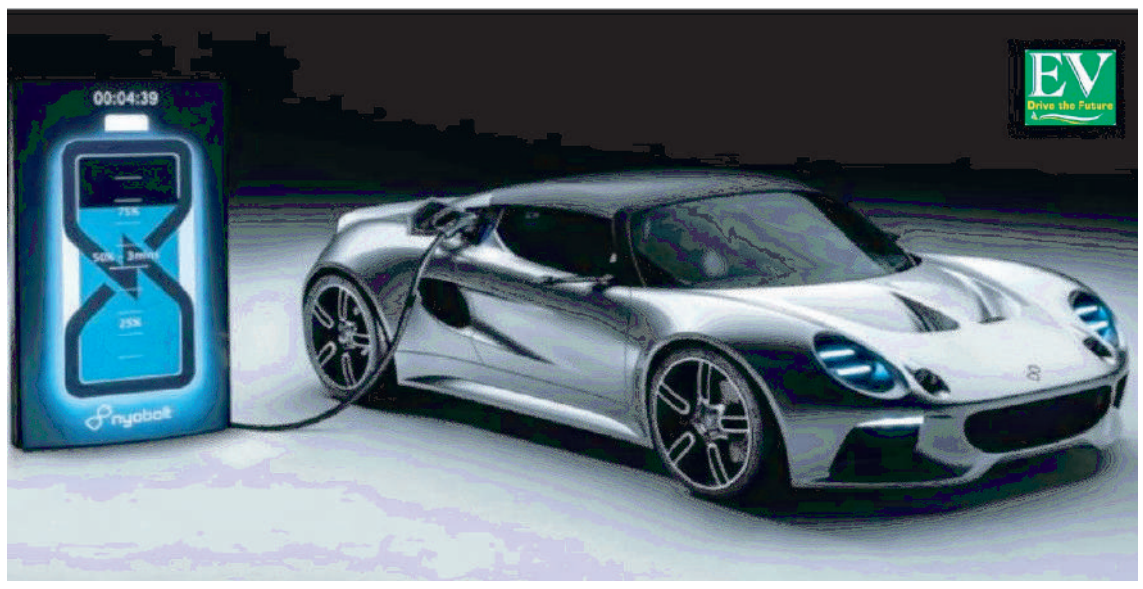

आवासीय भवनों के संघों के अनुरोध के आधार पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। एलटी कनेक्शन के तहत प्रत्येक ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग कनेक्शन की अनुमति है।

केईआरसी के नए नियमों में कहा गया है कि उपभोक्ताओं, प्रमोटरों, अधिभोगियों, मालिकों और संघों को ऐसे ईवी चार्जिंग स्टेशन कनेक्शनों की संख्या का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उन्हें यह तय करने की आवश्यकता है कि वे एकल बिंदु कनेक्शन चाहते हैं या प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग-अलग कनेक्शन चाहते हैं।

नए नियमों में कहा गया है कि सामान्य क्षेत्रों में नए कनेक्शन के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम से विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा या नए मीटर में तार जोड़ने के लिए पैनलों को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है।

नए मानदंडों में कहा गया है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन/नॉनपॉइंट को स्वीकृत लोड से परे मौजूदा प्रतिष्ठानों में जोड़ने की अनुमति है या यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक डिस्कॉम की मंजूरी से मीटर लोड बढ़ा सकता है।

केईआरसी के नए मानदंडों में कहा गया है कि बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग की जगह रखने वाले फ्लैट मालिक दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं और उन्हें ऐसी इकाइयों को उनके मौजूदा स्वीकृत लोड से परे या यदि आवश्यक हो तो बढ़े हुए स्वीकृत लोड के साथ जोड़ने की अनुमति है। उन्हें ईवी चार्जिंग टैरिफ के तहत एक नया कनेक्शन चुनने की भी अनुमति है।

जेएसडब्लू महाराष्ट्र में लगाएगी बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट, सरकार से मिली मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जिंदल साउथ वेस्ट समूह की कंपनियों जेएसडब्लू एनर्जी और जेएसडब्लू ग्रीन मोबिलिटी को महाराष्ट्र में नया प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जेएसडब्लू एनर्जी नागपुर में लिथियम-आयन बैटरी प्लांट लगाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएसडब्लू ग्रीन मोबिलिटी छत्रपति संभाजी नगर में 27,200 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहनों, चार्जर और मॉड्यूल के लिए प्लांट लगाएगी।

हाल ही में महाराष्ट्र में इन दोनों कंपनियों समेत 7 नई निवेश परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। सरकार की उद्योग संबंधी कैबिनेट उप-समिति ने राज्य के लिए कुल 81,167 करोड़ रुपये के निवेश और 23,136 रोजगार अवसरों को मंजूरी दी है। इस निवेश से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में 75,632 करोड़ रुपये और 19,000 रोजगार अवसर पैदा होंगे। सभी निवेश हरित ऊर्जा, हरित गतिशीलता और एफएबी/सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्रों में हैं।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में भारत का अग्रणी राज्य है, जो पिछले साल 3.7 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचकर दूसरे स्थान पर रहा और इसकी हिस्सेदारी 11 प्रतिशत रही। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल के पहले 7 महीनों में पूरे भारत में 10.6 लाख ईवी बेचे गए हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में बेचे गए 8.4 लाख की तुलना में साल-दर-साल आधार पर 27 प्रतिशत अधिक है।

एल5 ईवी वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए ठुकराल इलेक्ट्रिक और मुफिन ग्रीन फाइनेंस ने की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

ठुकराल इलेक्ट्रिक ने विशेष रूप से वंचित ग्राहक वर्गों के लिए एल5 ईवी वित्तपोषण के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए मुफिन ग्रीन फाइनेंस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक की तकनीकी क्षमता और मुफिन ग्रीन फाइनेंस की वित्तीय विशेषज्ञता बीच तालमेल का उद्देश्य भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक के संस्थापक जितेंद्र ठुकराल ने कहा, "मुफिन ग्रीन फाइनेंस के साथ एकजुट होकर, हम न केवल वित्त के भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि एक हरित कल को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

कंपनी के इशांक सुनेजा ने कहा कि मुफिन ग्रीन फाइनेंस के साथ यह साझेदारी एल5 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाजनक और सुलभ वित्तपोषण विकल्प चाहने वाले अनगिनत व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए तैयार है।

इलेक्ट्रिक कारों के टायर पेट्रोल कारों के मुकाबले क्यों जल्दी घिस जाते हैं

इलेक्ट्रिक कारों के टायर पेट्रोल या डीज़ल कारों की तुलना में ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं। अगर पेट्रोल कार के टायर 40,000 किलोमीटर चलने के बाद बदलने पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार के टायर सिर्फ़ 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार का वजन इतना ज़्यादा होता है कि उसके टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार के भारी वजन की वजह लिथियम बैटरी है। बैटरी के साथ-साथ कई और डिवाइस भी होती हैं, जिसकी वजह से कार का वजन बढ़ जाता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों में मोटर भी होती है, जिसकी वजह से टायर जल्दी घिस जाते हैं।

लेकिन पेट्रोल या डीज़ल कारों में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक वाहनों में टायरों के तेजी से घिसने का एक और कारण उनका उच्च टॉर्क है। इलेक्ट्रिक कारों में मोटर होती है जो पहियों को तेजी से घुमाती है, जिससे सड़क पर पहियों का घर्षण अधिक होता है। अगर आपके आस-पास की सड़क अच्छी नहीं है तो इलेक्ट्रिक कारों के टायर बहुत कम समय में खराब हो जाते हैं।

क्यों आज एक दशक बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत में विशेषज्ञता रखने वाली विशेष कार्यशालाओं की आवश्यकता आन पड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

जैसे-जैसे दुनिया टिकाऊ परिवहन की ओर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, विशेष रूप से हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में, जिसमें इलेक्ट्रिक 3-पहिया और ई-ऑटो शामिल हैं।

विशेष कार्यशालाओं की कमी उनके अपनाने और रखरखाव में बाधा डालती है। यहाँ हम ईवी को समर्पित भौतिक कार्यशालाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो ई-रिक्शा (एल3), ई-लोडर (एल3), ई-ऑटो (एल5) और अन्य छोटी क्षमता वाले 4 पहिया वाहनों जैसे इलेक्ट्रिक 3-पहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

01. मौजूदा ईवी निर्माताओं के कार्यशालाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :

- ईवी-विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी
- अपर्याप्त उपकरण और औजार
- ईवी तकनीक के साथ अपर्याप्त अनुभव
- ईवी भागों और आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित पहुँच

02. आज के समय मे विशेष विशेषज्ञ ईवी कार्यशालाओं के जरूरत और लाभः

- नई ईवी तकनीक और इसकी मरम्मत में विशेषज्ञता
- कुशल सेवा के लिए उपयुक्त उपकरण और औजार
- तेज़ निदान और बेहतर मरम्मत समय
- ईवी-विशिष्ट भागों, छोटे-छोटे पार्ट्स और उनके आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँच

03. ये विशेष कार्यशालाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगीः

- ईवी-प्रशिक्षित तकनीशियन और कर्मचारी
- समर्पित ईवी सर्विस बे और उपकरण
- यदि आवश्यक हो तो ईवी-विशिष्ट उपकरण और डायग्नोस्टिक सॉफ़्टवेयर
- ईवी भागों और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँच
- ईवी पर नियमित प्रशिक्षण और अपडेट प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर और अन्य हल्के वाणिज्यिक ईवी की बढ़ती मांग ने विशेष कार्यशालाओं की स्थापना को आवश्यक बना दिया है। ये कार्यशालाएँ कुशल और प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करने, ईवी को अपनाने में वृद्धि करने और उनमें विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, उपकरण और ज्ञान प्रदान करेंगी। ईवी-विशिष्ट कार्यशालाओं में निवेश करके, कोई भी व्यक्ति टिकाऊ परिवहन क्रांति का समर्थन कर सकता है और इस तेजी से बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

जैसा कि बाजार से पता चलता है बिक्री और कार्यशाला बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

इस अंतर को पाटने के लिए ईज़ेड-ऑटोशाला का ऑटोअड्डा वास्तव में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए एक समाधान लेकर आया है, खासकर इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर स्पेस में। मल्टी-ब्रांड फ्रैंचाइज़ी कार्यशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करके, ऑटोअड्डा विशेषकर ईवी सेवा और समर्थन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है।

01. मल्टी-ब्रांड सहायता: ऑटोअड्डा की फ्रैंचाइज़ वर्कशॉप इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स की सभी सेवा आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है और विभिन्न ईवी ब्रांड्स की सेवा कर सकती है।

02. मानकीकृत सेवा: ऑटोअड्डा सभी फ्रैंचाइज़ वर्कशॉप में लगातार, उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा सुनिश्चित करता है, जिससे ईवी मालिकों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण होता है।

03. प्रशिक्षित तकनीशियन: ऑटोअड्डा के प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीशियनों को ईवी-विशिष्ट मरम्मत और रखरखाव को संभालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं।

04. असली पुर्जों तक पहुँच: ऑटोअड्डा का नेटवर्क असली ईवी पुर्जों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है, डाउनटाइम को कम करता है और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

05. सुविधा: कई स्थानों के साथ, ऑटोअड्डा ईवी सेवा और सहायता तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है, जिससे रेंज की चिंता कम होती है और स्वामित्व का अनुभव बेहतर होता है।

ऑटोअड्डा की पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है:

01. ईवी अपनाने में तेज़ी लाना: विश्वसनीय सेवा और सहायता प्रदान करके, ऑटोअड्डा रेंज की चिंता को कम करने में मदद करता है और अधिक लोगों को ईवी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

02. सतत विकास को बढ़ावा देना: ईवी पर ऑटोअड्डा का ध्यान स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है और सतत परिवहन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल का समर्थन करता है।

03. छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना: ऑटोअड्डा का फ्रैंचाइज़ी मॉडल छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को ईवी क्रांति में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे नए अवसर और नौकरियाँ पैदा होती हैं।

ईवी सेवा और समर्थन में अंतर को भरकर, ईज़ेड-ऑटोशाला का ऑटोअड्डा इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर बाजार और व्यापक ईवी पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है।

आज के शैक्षणिक माहौल में बहुविषयक शिक्षा का महत्व

विजय गर्ग

बहुविषयक शिक्षा, जो अध्ययन के कई क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि और तरीकों को जोड़ती है, इन बहुमुखी मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक बहुमुखी और अनुकूली विचारकों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। बहु-विषयक शिक्षा को अपनाकर, शैक्षणिक संस्थान छात्रों को न केवल आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने के लिए तैयार कर सकते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने और प्रगति करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं।

बहुविषयक शिक्षा, जो अध्ययन के कई क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि और तरीकों को जोड़ती है, इन बहुमुखी मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक बहुमुखी और अनुकूली विचारकों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तेजी से परस्पर जुड़ी और जटिल दुनिया में, पारंपरिक शैक्षिक मॉडल जो एक ही अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अब पर्याप्त नहीं हैं। आज की चुनौतियाँ वैश्विक स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय स्थिरता से लेकर तकनीकी प्रगति और सामाजिक असमानता और सीखने के लिए अधिक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण तक हैं। बहुविषयक शिक्षा, जो अध्ययन के कई क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि और तरीकों को जोड़ती है, इन बहुमुखी मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक बहुमुखी और अनुकूली विचारकों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। बहु-विषयक शिक्षा को अपनाकर, शैक्षणिक संस्थान छात्रों को न केवल आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने के लिए तैयार कर सकते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने और प्रगति करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सहयोग का पोषण करता है, शिक्षार्थियों को लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण से लैस करता है। इंडिया टुडे.इन ने बहु-विषयक को समझने के लिए बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन, प्रतीक मोदी से बात की। आज के शैक्षणिक माहौल में शिक्षा. आप बहु-विषयक शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं, और आप इसे आज के शैक्षणिक माहौल में क्यों आवश्यक मानते हैं? बहु-विषयक शिक्षा समग्र शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विषयों से ज्ञान और पद्धतियों को एकीकृत करती है। यह छात्रों को विषयों के बीच संबंध बनाने, उनकी आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के तेजी से विकसित हो रहे शैक्षणिक माहौल में, यह दृष्टिकोण आवश्यक है क्योंकि यह छात्रों को जटिल, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है जो एक अनुशासन में अच्छी तरह से फिट नहीं होती हैं। यह नवाचार, अनुकूलनशीलता और व्यापक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देता है, स्नातकों को विविध पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने और वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक बहुमुखी कौशल से लैस करता है। पारंपरिक शैक्षणिक कठोरता से समझौता किए बिना संस्थान अनुभवात्मक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? संस्थान ऐसे कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करके अनुभवात्मक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत कर सकते हैं जो पारंपरिक शैक्षणिक कठोरता को प्रतिस्थापित करने के बजाय पूरक करते हैं। इसे विभिन्न तरीकों से हासिल किया जा सकता हैः परियोजना-आधारित शिक्षाः वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं को शामिल करना जिनके लिए छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक परिदृश्यों में लागू करने की आवश्यकता होती है। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकमः इंटर्नशिप की पेशकश करने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करना जो अकादमिक निगरानी बनाए रखते हुए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। सामुदायिक विसर्जनः सामुदायिक विसर्जन और सहभागिता परियोजनाओं को एकीकृत करना जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हों, छात्रों को सीखने और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। सिमुलेशन और केस स्टडीजः कक्षा के भीतर वास्तविक दुनिया की स्थितियों की नकल करने के लिए सिमुलेशन, रोल-प्ले और केस स्टडीज का उपयोग करना। सहयोगात्मक शिक्षाः कार्यस्थल की गतिशीलता और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने के लिए समूह कार्य और अंतःविषय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। बहु-विषयक और अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करते समय शिक्षकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? कार्यान्वयन करते समय शिक्षकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैबहुविषयक और अनुभवात्मक शिक्षा, जिसमें शामिल हैं: पाठ्यचर्या को पुनः डिज़ाइन करना: एक सामंजस्यपूर्ण पाठ्यक्रम बनाना जो कई विषयों और अनुभवात्मक तत्वों को एकीकृत करता है, जटिल हो सकता है। इस पर काबू पाने के लिए सीखने के परिणामों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, संकाय के बीच सहयोग और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। संसाधन की कमीः अनुभवात्मक शिक्षा के लिए अक्सर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फंडिंग, प्रौद्योगिकी और बाहरी संगठनों के साथ साझेदारी। अनुदान सुरक्षित करना, उद्योग साझेदारी बनाना और पूर्व छात्र नेटवर्क का लाभ उठाना इन बाधाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। मूल्यांकन कठिनाइयाँ: अनुभवात्मक और बहु-विषयक शिक्षा के परिणामों को मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्पष्ट रूब्रिक्स विकसित करना, चिंतनशील मूल्यांकन का उपयोग करना और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना अधिक व्यापक मूल्यांकन विधियां प्रदान कर सकता है। संकाय प्रशिक्षणः इन शिक्षण दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की आवश्यकता हो सकती है। कार्यशालाओं, अंतर-विषयक सहयोग और अनुदेशात्मक डिजाइन विशेषज्ञों के समर्थन की पेशकश से संकाय की तैयारी में वृद्धि हो सकती है। छात्र अनुकूलनः पारंपरिक शिक्षण विधियों के आदी छात्र अनुभवात्मक शिक्षा की स्व-निर्देशित प्रकृति के साथ संघर्ष कर सकते हैं। स्पष्ट मार्गदर्शन, मजबूत अनुभव और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देने से छात्रों को अनुकूलन में मदद मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा का दृष्टिकोण भारतीय संस्थानों की तुलना में कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा का दृष्टिकोण अक्सर लचीलेपन, नवाचार और अंतर-विषयक सहयोग पर जोर देता है। मुख्य अंतरों में शामिल हैंः पाठ्यक्रम में लचीलापनः अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अक्सर लचीले पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यापक शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत, भारतीय संस्थानों में पारंपरिक रूप से अधिक कठोर, विशिष्ट कार्यक्रम हैं, हालांकि यह धीरे-धीरे बदल रहा है। अंतःविषय कार्यक्रमः अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने अक्सर अंतःविषय कार्यक्रम और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संस्थान समान मॉडल अपनाने लगे हैं लेकिन अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। अनुभवात्मक शिक्षण एकीकरणः कई अंतरराष्ट्रीय संस्थान इंटर्नशिप, सह-ऑप्स और वैश्विक अध्ययन कार्यक्रमों के माध्यम से अनुभवात्मक सीखने को प्राथमिकता देते हैं। जबकि भारतीय संस्थान तेजी से अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व को पहचान रहे हैं, वहाँ अक्सर कम संरचित अवसर उपलब्ध होते हैं। उद्योग भागीदारीः व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अक्सर उद्योग और सरकारी क्षेत्रों के साथ सहयोग करते हैं। भारतीय संस्थान इन साझेदारियों को बढ़ा रहे हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाए जाने वाले पैमाने और गहराई से मेल खाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संकाय प्रशिक्षण और विकासः बहु-विषयक और अनुभवात्मक शिक्षा का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अक्सर संकाय विकास में भारी निवेश करते हैं। भारतीय संस्थान इस क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं लेकिन अभी भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने प्रयासों का विस्तार करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षण विधियों को बढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मॉडल से क्या सीख सकती है? भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षण विधियों को बढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मॉडल से कई मूल्यवान सबक ले सकती हैः प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा (पीबीएल): पीबीएल पर जोर देने से छात्रों को मदद मिल सकती हैवास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए सैद्धांतिक ज्ञान। भारतीय शिक्षा संरचित पीबीएल ढांचे को अपना सकती है जो सहयोग, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। सामुदायिक जुड़ावः कई अंतरराष्ट्रीय संस्थान नागरिक जिम्मेदारी और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देते हुए, शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ सामुदायिक जुड़ाव को एकीकृत करते हैं। भारतीय संस्थान सेवा-शिक्षण परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं जो स्थानीय समुदाय के मुद्दों को संबोधित करते हैं, छात्रों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। वैश्विक एक्सपोजरः अंतर्राष्ट्रीय मॉडल में अक्सर विदेश में अध्ययन कार्यक्रम और वैश्विक इंटर्नशिप शामिल होते हैं। भारतीय शिक्षा विनिमय कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बना सकती है, जिससे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव और व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलेगा। प्रौद्योगिकी और सिमुलेशन का उपयोगः सिमुलेशन, वर्चुअल लैब और ऑनलाइन सहयोगी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम है। भारतीय संस्थान इन प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ा सकते हैं, जिससे व्यापक शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके। संकाय विकास में निवेशः शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्थान संकाय को अनुभवात्मक शिक्षण तकनीकों को अपनाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अद्यतन रहने में मदद करने के लिए मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित कर सकते हैं। मूल्यांकन नवाचारः अंतर्राष्ट्रीय मॉडल अक्सर विविध मूल्यांकन विधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें चिंतनशील पत्रिकाएँ, सहकर्मी समीक्षाएँ और परियोजना मूल्यांकन शामिल हैं। अनुभवात्मक शिक्षण परिणामों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए भारतीय शिक्षा इन नवीन मूल्यांकन रणनीतियों को अपना सकती है।

सेवानिवृत्तप्रधानाचार्यशैक्षिक स्तंभकारमलोट

संपादकीय

राहुल का नया चक्रव्यूह

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बजट पर बोलना था, लेकिन उन्होंने महाभारत कालीन चक्रव्यूह का नया रूपक ही गढ़ दिया। हजारों साल पुराने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया था। उसका नियंत्रण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि के हाथों में था। आज का चक्रव्यूह भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आदि छह हाथों में है। दो शेष नाम देश के बड़े उद्योगपतियों के हैं, जिनका नाम सदन में नहीं लिया जा सकता था। स्पीकर ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला दिया, लेकिन राहुल गांधी उनका एक बार नाम ले चुके थे। फिर उन्हें ए-1, ए-2 नामकरण दिया। राहुल गांधी ने यह रूपक क्यों गढ़ा? क्या आज का चक्रव्यूह भी किसी को हताहत करने को रचा गया है? संसद में ऐसी हिंसकवादी राजनीति के कोई मायने नहीं हैं, लिहाजा स्पीकर नेता प्रतिपक्ष को बार-बार सलाह देते रहे कि एक बार और सदन के नियमों को नेता प्रतिपक्ष पढ़ लें। जाहिर है कि राहुल गांधी बार-बार नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं। बहरहाल नए चक्रव्यूह के संदर्भ में जवाब राहुल ही देंगे, लेकिन उनकी राजनीति समझ में जरूर आती है कि 2024 के आम चुनाव की तरह वह अब भी एक नेरेटिव देश में फैलाना चाहते हैं। वह नेरेटिव भाजपा के हिंदुत्व और सवर्णवाद की काट साबित हो सकता है, ऐसी राहुल गांधी की उम्मीद है। उनकी राजनीति जातीय जनगणना की है, जबकि कांग्रेस में उनके पुरखे ऐसे जातिवाद के खिलाफ थे और ऐसी जनगणना को कभी भी लागू नहीं किया। कांग्रेस की विरासत ही कांग्रेस के विपरीत है। राहुल गांधी का फोकस पिछड़े, दलित, आदिवासी पर ज्यादा है।

उन्होंने अपने 46 मिनट के भाषण का सारांश यह रखा कि गरीब, पिछड़े, दलित, युवा, किसान समेत पूरा देश भय के चक्रव्यूह में है। अग्निवीरों को भी चक्रव्यूह में फंसाया गया है। प्रधानमंत्री जिस कमल के फूल (भाजपा का चुनाव चिह्न) को लहराते रहते हैं, उसी के आकार वाला चक्रव्यूह है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सियासत के मुताबिक हिंदू धर्म का अपमान किया है। भाजपा ने यूं पलटवार करते हुए कहा है कि जिस फूल को ब्रह्मा जी, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती ने अपना आसन बनाया, पवित्रता के प्रतीक उसी फूल को राहुल गांधी ने 'हिंसक' करार दिया। यह धार्मिक अपमान राहुल की राजनीति के मुताबिक है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर संभवतः 2.5 फीसदी ही बोला। सिर्फ शिक्षा का आवंटन ही उन्हें याद रहा। बजट की 'हलवा सेरेमनी' में भी उन्होंने जातिवाद को घुसेड़ कर कहा कि जो 20 अधिकारी देश का बजट तैयार करते हैं, उनमें कोई भी ओबीसी, दलित या आदिवासी अफसर नहीं है, जबकि इन समुदायों की आबादी देश की 73 फीसदी है। सिर्फ 2-3 फीसदी लोग ही 'हलवा' बनाते हैं, वे ही बांटते हैं और वे ही खा जाते हैं। देश की 73 फीसदी आबादी को 'हलवा' नहीं मिल रहा है। राहुल का कथन देश के संसाधनों और शक्तियों की व्याख्या कर रहा है। उनका जातिवाद भी इसी आधार पर टिका है कि जो देश में बहुसंख्यक हैं, वे ही वंचित और विपन्न हैं। शायद राहुल गांधी को यह याद नहीं रहा कि बजट से जुड़ा 'राजनीतिक हलवा' तो बीते 70 सालों से अधिक समय से बांटा जा रहा है। इस दौरान सर्वाधिक सरकारें कांग्रेस की रही हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान 2011 की जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई गई थी। उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? कर्नाटक में जब सिद्धारमैया पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी। आज भी वह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े आज तक भी जारी नहीं किए गए। कांग्रेस या राहुल गांधी स्पष्ट कर सकते हैं कि उनके जातिवाद का यथार्थ क्या है? राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि जो मध्यवर्ग प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का समर्थक था, आज वह 'इंडिया' की तरफ आ रहा है, क्योंकि मध्यवर्ग की पीठ और छाती में छुरा घोंपा गया है। बहरहाल हमारा सरोकार राहुल के चक्रव्यूह से है कि उसके मायने क्या हैं?

राय

हमारी गूंज भी सुनो

हिमाचल सरकार की इच्छाशक्ति का परिचय देती 'मंडे मीटिंग' हमेशा कुछ निष्कर्ष, कुछ परामर्श और कुछ अर्श खोजती है, लेकिन शिमला के कान राज्य को पूरी तरह सुन नहीं पाते। ब्यास नदी में वन विभाग खनन पर उतरेगा, यह एक नीतिगत फैसला है, लेकिन इसी विभाग से संबंधित निगम वर्षों से आश्वस्त करने के बावजूद इमारती लकड़ी की हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। हिमाचल के वास्तुशास्त्र में लकड़ी से जुड़ी कई तरह की निर्माण शैलियां विकसित हुईं, मगर अब चाह कर भी उपभोक्ता अपनी जरूरतों की इमारती लकड़ी विभाग से नहीं ले पाता। विभाग वर्षों से पौधारोपण कर रहा है, लेकिन नए दरख्तों का हिसाब नहीं दे पाता। जंगल में पहले जड़ी-बूटियों का एक विस्तृत भंडार था, लेकिन अब ठीक से कुछ बता नहीं पाता। हैरान कर देने वाले हादसों का सीधा अपराध भले ही वन विभाग के पेड़ पर आता हो, लेकिन इसके लिए न उसकी कोई जिम्मेदारी और न ही हर्जाना अदा करने का कोई प्रावधान। पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला के एक क्लब से उखड़ कर एक पेड़ कला संग्रहालय के मुख्य गेट पर आने वालों के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन वन संरक्षण के नाम पर विभाग कानों में रुई डाल कर कहीं दूर बैठा है। कुछ महीने पहले इसी शहर में पेड़ ने अपनी ताकत बुलंद करके शहीद स्मारक के एक हिस्से की छत उखाड़ दी। वार म्यूजियम के प्रवेश पर टूटी हुई छत ने एक पूरा पर्यटक सीजन गुजार दिया, लेकिन अब मरम्मत की जिम्मेदारी में पांच लाख की अनुमानित लागत का वारिस वन विभाग नहीं। आखिर यह महकमा इतना खुदगर्ज, संवेदनहीन और लापरवाह कैसे हो सकता है। बहरहाल वन महोत्सव के मनोरंजन में उखड़ते पेड़ों की क्या मजाल जो इन्हें ठिकाने लगाया जाए।

अब खनन में वन विभाग के पांव कौनसे घुंघरू पहनकर चलता है, यह देखना होगा। 'मंडे मीटिंग' के पास मंत्रिमंडल की बैठकों से कहीं अधिक शक्ति है और यह अक्सर इसके एक्शन से साबित होता है, लेकिन जब कहीं जोगिंद्रनगर का घातक पीलिया दो लोगों को डस लेता है, तो हंगामा होना चाहिए। सतत प्रयास से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जोगिंद्रनगर की बीएससी नर्सिंग छात्रा का कसूर यह कि उसने सार्वजनिक जल के नल से पानी पीया था। उसके अभिभावकों का यह कसूर कि पीलिया से बिगड़ती हालत से मजबूर वे उसे प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कालेजों से दूर पीजीआई ले जा रहे थे, तो उसकी मौत हो गई। काश! प्रदेश की जल प्रयोगशालाओं ने पानी का सही और समय पर परीक्षण किया होता। काश! जोगिंद्रनगर से टांडा मेडिकल कालेज तक की औकात पर इतना भरोसा होता कि पीलिया से यह बच्ची बच जाती। सोमवार के दिन नगरोटा बगवां के व्यापारी रोष रैली क्यों निकाल रहे थे, अगर यह गूंज मंडे मीटिंग तक पहुंच जाते तो इनसाफ का रुतबा बढ़ जाएगा। हिमाचल के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट घराने के साथ चौदह करोड़ की ठगी का मामला आए काफी समय गुजर गया, मगर नगरोटा बगवां का ही ठग आराम से पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच नगरोटा ने कई जश्न मना लिए, सरकारी घोषणाओं के अवसर बता दिए, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी का वांछित अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। या तो कांगड़ा में एक और पुलिस जिला बना देना चाहिए, ताकि अपराध के सामने विभाग का भी मनोबल ऊंचा रहे, वरना हर नागरिक को अपने लिए खुद ही सुरक्षा दीवारों का प्रबंध करना होगा। हमारा मानना और विश्वास है कि 'मंडे मीटिंग' से प्रशासन व सुशासन के वजूद को कुछ साहसिक लक्ष्य मिलेंगे। हम कानून, प्रशासन और प्रबंधन की औपचारिकता से व्यावहारिक व्यवस्था तक पहुंचें, इसके लिए एक स्वाभाविक संस्कृति की जरूरत है, मगर दुख होता है जब किसी डीसी कार्यालय भवन की दीवारों पर पेड़, परिसर में झाडियां और प्रांगण में आवारा पशु घूमते हैं। आखिर इसके लिए भी निर्देश चाहिए, तो प्रदेश के लिए हर दिन की सक्रियता और जवाबदेही चाहिए।

स्पोर्ट्स कमेंटेटर - स्पोर्ट्स कमेंटेटर कैसे बनें

विजय गर्ग

खेल टिप्पणीकार (स्पोर्टकास्टर्स) किसी खेल खेल या आयोजन की घटनाओं का वर्णन करते हैं। वे कार्यक्रम को रेडियो पर प्रसारित कर सकते हैं, जिससे श्रोता को यह समझने के लिए पर्याप्त विवरण मिल सके कि क्या हो रहा है। खेल कमेंटेटर टेलीविजन में भी काम करते हैं, जो खेल के साथी के रूप में कमेंट्री करते हैं। छोटी कार्रवाई की अवधि में, एक टिप्पणीकार खेल में वर्तमान घटनाओं या खेल के इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात कर सकता है। आज के समय में खेल के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए करियर की ढेरों संभावनाएं हैं। उन्हें अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञान के साथ-साथ देश-दर-देश के आधार पर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। खेल कमेंटेटर पात्रता शैक्षणिक योग्यता स्पोर्ट्स कमेंटेटर पाठ्यक्रमों के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता विषयों के साथ 10वीं या 12वीं कक्षा है। खेल कमेंटेटर के लिए आवश्यक कौशल खेल टिप्पणीकारों के पास बोलने, लिखने, सुनने और पारस्परिक कौशल, अनुसंधान क्षमता और मीडिया उत्पादन कौशल होना चाहिए। उन्हें मीडिया उत्पादन, संचार और प्रसार तकनीकों और तरीकों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें दूरसंचार में भी अच्छा होना चाहिए जैसे कि दूरसंचार प्रणालियों के प्रसारण, प्रसारण, स्विचिंग, नियंत्रण और संचालन का ज्ञान। उनमें त्वरित सोच कौशल होना चाहिए क्योंकि कमेंट्री के दौरान उनकी गति एक टीम से दूसरी टीम में अचानक बदल जाती है, किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, अचानक मौसम बदल जाता है। अप्रत्याशित या यहां तक कि दर्दनाक घटित होने पर तुरंत सोचने और शांत और पेशेवर बने रहने की क्षमता स्पोर्ट्सकास्टर्स के लिए एक मूल्यवान कौशल है। स्पोर्ट्स कमेंटेटर कैसे बनें? स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। स्टेप 1 स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने के लिए आपके बोलने के तरीके के साथ-साथ आपके पैरों पर खड़े होकर सोचने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। उन्हें खेल के अच्छे ज्ञान के साथ-साथ पत्रकारिता में भी कुछ कौशल की आवश्यकता है। चरण दो खेल कमेंटेटर की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए; पत्रकारिता, प्रसारण पत्रकारिता, या संचार में चार साल की स्नातक की डिग्री पूरी करनी चाहिए। कुछ पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं। डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, छात्रों को एक विषय के रूप में पत्रकारिता या संचार के साथ 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैंः बी ० ए। (पत्रकारिता के साथ अंग्रेजी) प्रसारण पत्रकारिता में डिप्लोमा बी ० ए। (पत्रकारिता एवं जनसंचार) चरण 3 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के इच्छुक छात्र इन्हें चुन सकते हैं। पत्रकारिता और संचार में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कई संस्थान हैं। कुछ मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं जिन्हें उम्मीदवार अपना सकते हैं। मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों

के लिए, उन्हें पत्रकारिता और संचार जैसे संबंधित विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैंः एम.ए. (प्रसारण संचार) एम.ए. (विज्ञापन और संचार प्रबंधन) एम.ए. (प्रसारण पत्रकारिता) खेल कमेंटेटर के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फ़रीदाबाद एमआईटी जनसंवाद कॉलेज, लातूर एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म, पुणे एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली। खेल कमेंटेटर नौकरी विवरण कुछ खेल टिप्पणीकार प्रसारण मीडिया उद्योग में अन्य भूमिकाएँ निभाते हैं। वे एक कॉलम लिख सकते हैं, या एक प्रसारण रिपोर्टर के रूप में काम कर सकते हैं। कुछ खेल उद्योग में कार्यरत हैं और कमेंटेटर के रूप में काम करते हैं। उनमें से कुछ को अक्सर खेल सुविधाओं, जैसे कि एरेना या रेस क्लब द्वारा नियोजित किया जाता है। इन्हें उद्घोषक के नाम से भी जाना जाता है। खेल कमेंटेटर कैरियर संभावनाएं खेल कमेंटेटरों के पास रेडियो स्टेशनों में नौकरी का विकल्प एक कमेंटेटर के रूप में करियर का प्रवेश बिंदु माना जा सकता है। बाद में वे टीवी या अन्य निजी चैनलों/मीडिया की ओर रुख कर सकते हैं। उन्हें मैच पर टिप्पणी करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो या टीवी स्टेशनों द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। उनके पास स्टार स्पोर्ट्स, ईएसपीएन टेन स्पोर्ट्स, ज़ी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स चैनल पर भी खेल कमेंटेटर हैं। उन्हें खेल संगठनों और नेटवर्क द्वारा लाइव एक्शन यानी खेल आयोजनों के खेल-दर-खेल को कवर करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है। टिप्पणीकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों के लिए टिप्पणियाँ या कॉलम लिख सकते हैं। अधिकांश मामलों में, पूर्व खिलाड़ी सेवानिवृत्ति के बाद कमेंट्री को एक पेशे के रूप में अपनाते हैं। खेल कमेंटेटर वेतन खेल कमेंटेटरों के लिए वेतनमान काफी भिन्न होता है, जो मुख्य रूप से रोजगार के स्थान और उनकी अपनी गुणवत्ता और प्रस्तुति पर निर्भर करता है। औसतन, कमेंटेटर प्रतिदिन 5000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच कमाते हैं। लेकिन जाने-माने लोग एक दिन के लिए 25,000 रुपये से बेहतर रकम कमाते हैं। उनकी वार्षिक आय इस बात पर निर्भर करती है कि आपको साल में कितने दिनों के लिए काम मिलता है।

सेवानिवृत्तप्रधानाचार्यशैक्षिकस्तंभकारमलोट

उधार का मायाजाल : विजय गर्ग

आधुनिकता की होड़ में जीवन इतनी तेजी से भाग रहा है कि अब मनुष्य को हर चीज चुटकियों में चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आजकल कोई अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए धैर्य रखना नहीं चाहता। सबको जैसे एक अलादीन का चिराग चाहिए कि इधर इच्छा व्यक्त की और उधर पूरी हो जाए । यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर लोगों के भीतर इतनी तेजी और इतनी हड़बड़ी क्यों है? सब कुछ तुरंत और बहुत तेज रफ्तार से क्यों चाहिए? जबकि सच यह है कि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि इच्छा जाहिर की और किसी 'जिन्न' की तरह कोई प्रकट हुआ और उसने तुरंत इच्छा पूरी कर दी। मगर आजकल यह 'जिन्न' वाला काम कुछ बैंक वाले करने का दावा करने लगे हैं । व्यक्ति की हर छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की उनके पास फेहरिस्त होती है और उसे वे ईएमआइ यानी मासिक किस्त में बांधकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। दुनिया जहान की किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस उसकी किस्तें बंधवा ली जाए और चीज हमारे घर में होगी। मसलन, सोफा, टीवी, फ्रिज, माइक्रो वेव, मोबाइल आदि कुछ भी । घर तो किस्तों पर मिलता ही रहा है। फिर अपने - अपने दफ्तरों में रगड़ते रहा जाए खुद को और एक लंबे अरसे तक भरते रहा जाए किस्त-दर- किस्त अपने माथे पर बोझ की तरह पड़ चुके ऋण की । आश्चर्य तो तब होता है जब हमको यह पता चलता है कि हमारी आमदनी से ज्यादा हमारे उधार हैं और यह एक मायाजाल है, जिसमें हम बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। दूसरी ओर, आवश्यकताएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और न ही उधार लेने का सिलसिला ही कभी रुकता है ।

एक तरफ होती है मासिक किस्त और दूसरी तरफ होता है क्रेडिट कार्ड का बिल। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसकी टोपी उसके सिर का कोई खेल हो गई है जिंदगी... 'न सांस लेने की फुर्सत है न जीने का अहसास', बस हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है हम सबकी जिंदगी। कहने का मतलब यह है कि बाजारवाद से इतने घिरे हुए है हम कि अब जीवन पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो गया है। बात सेहत की हो तो स्वास्थ्य बीमा, गाड़ी खरीद ली गई हो तो कार बीमा, घर खरीदा हो तो उसका बीमा और यहां तक कि हमारे मर जाने के बाद के लिए भी जीवन - बीमा । यह बात अब बहुतों की जुबान या दिमाग में है कि केवल जिंदगी के साथ ही नहीं, जिंदगी के बाद भी । जीवन बीमा का तो फिर भी समझ में आता है जो हमारे बाद परिवार के काम आता है, लेकिन बाकी जरूरतें क्या इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें ईएमआई यानी मासिक किस्तों पर लिया जाना चाहिए ?

यह माना जा सकता है कि मासिक किस्तों की व्यवस्था में पैसा थोड़ा-थोड़ा कटता है तो चीजों का बोझ महसूस नहीं होता । वह भी तब, जब हमारे घर में दो आमदनियां हों, अन्यथा एक ही आमदनी पर तो मासिक किस्तों का यह बोझ भारी पड़ने लगता है, क्योंकि यह किसी एक वस्तु से संबंधित नहीं होती, बल्कि अनेक वस्तुओं से संबंधित होती है । वह भी एक साथ। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तो तब होता है, जब दो- दो लोगों की आमदनी होते हुए भी लालच लोभ इतना अधिक बढ़ जाता है कि गैरजरूरी चीजों के लिए भी हम यानी मासिक किस्त और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ।

यह सोचने की जरूरत है कि बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता। कोरोना जैसी आपदा के बाद जब लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गईं, तब उनका क्या हाल हुआ, यह तो वे ही जानते हैं। विदेश में तो और भी बुरा हाल है। हमारे वृद्ध जनों ने यों ही कर्ज को खराब नहीं बताया है। कर्ज ही वह कारण है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है । फिर एक हम हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। जबकि हमारे आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं होती देखने-सुनने को मिल रही हैं कि कर्ज में डूबा कोई व्यक्ति नौकरी या रोजगार जाने के बाद मासिक किस्त या कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहा और इससे उपजे दबाव और तनाव ने उसकी जिंदगी लील ली। कोई गंभीर बीमारी का शिकार होकर और ज्यादा बड़े मकड़जाल में फंस गया तो कोई वक्त के थपेड़ों को सह नहीं सका और किसी ने कभी अकेले तो कभी परिवार सहित जान दे दी। जिंदा भर रह सकने के लिए किसी से उधार लेना अलग बात है, मगर यह कितना त्रासद है कि बहुत मामूली सुविधाओं या दिखावे के सामान खरीदने के लिए हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और होश तब आता है, जब हमारा गला कसने लगता है ।

सच यह है कि कुछ निजी और अहम जरूरतों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना रहा नहीं जा सकता। लेकिन समाज में हैसियत की बात, उसका दिखावा और दूसरों से प्रतियोगिता का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में अगर कोई दिखावे में विश्वास रखता है तो किस्त - दर - किस्त भरने के लिए उसे अपनी मेहनत की कमाई को यों ही खर्च करने में गुम होना पड़ेगा। अन्यथा सादा जीवन उच्च विचार का रास्ता हमेशा खुला है। कहा भी जाता है कि ' जिसकी जरूरतें कम हैं, उसके हाथ में दम है'।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक

नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST कम करने की मांग

परिवहन विशेष न्यूज

लाइफ इंश्योरेंस और मेडीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी की जीएसटी लगती है। अब प्रीमियम पर जीएसटी कम लगने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। इस पत्र में गडकरी ने नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया और जीएसटी कम करने की मांग की।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। इस पत्र में गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18 फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) हटाने का अनुरोध किया है।

कम होना चाहिए GST

गडकरी ने अपने पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया है। इसके लिए मंत्री ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का हवाला देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है।

ज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, " जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को 'कवर' करता है, उससे 'कवर' खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लेना चाहिए।

कर्मचारी संघ भी चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को हटाना चाहिए। वर्तमान में जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है।

मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी विकास में बाधक साबित हो रहा है। ऐसे में अनुरोध है कि लाइफ तथा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा।

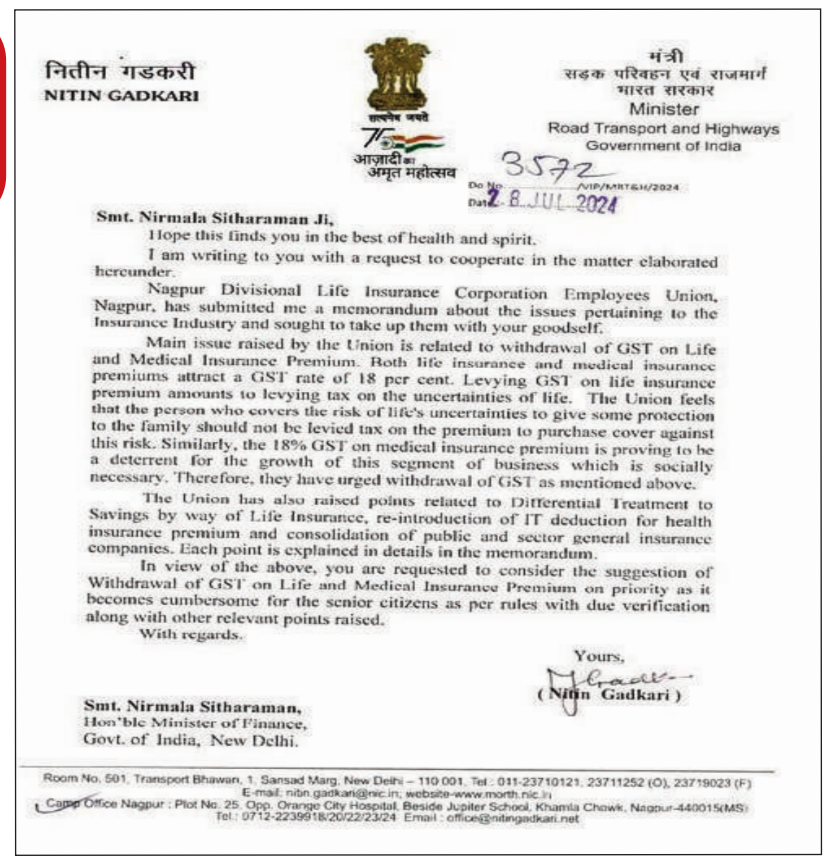

नितीन गडकरी
NITIN GADKARI

मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
भारत सरकार
Minister
Road Transport and Highways
Government of India

सत्यमेव जयते
आज़ादी का अमृत महोत्सव

Do No. 3572/VIP/MRT&H/2024
Date 28 JUL 2024

Smt. Nirmala Sitharaman Ji,

Hope this finds you in the best of health and spirit.

I am writing to you with a request to cooperate in the matter elaborated hereunder.

Nagpur Divisional Life Insurance Corporation Employees Union, Nagpur, has submitted me a memorandum about the issues pertaining to the Insurance Industry and sought to take up them with your goodself.

Main issue raised by the Union is related to withdrawal of GST on Life and Medical Insurance Premium. Both life insurance and medical insurance premiums attract a GST rate of 18 per cent. Levying GST on life insurance premium amounts to levying tax on the uncertainties of life. The Union feels that the person who covers the risk of life's uncertainties to give some protection to the family should not be levied tax on the premium to purchase cover against this risk. Similarly, the 18% GST on medical insurance premium is proving to be a deterrent for the growth of this segment of business which is socially necessary. Therefore, they have urged withdrawal of GST as mentioned above.

The Union has also raised points related to Differential Treatment to Savings by way of Life Insurance, re-introduction of IT deduction for health insurance premium and consolidation of public and sector general insurance companies. Each point is explained in details in the memorandum.

In view of the above, you are requested to consider the suggestion of Withdrawal of GST on Life and Medical Insurance Premium on priority as it becomes cumbersome for the senior citizens as per rules with due verification along with other relevant points raised.

With regards.

Yours,
(Nitin Gadkari)

Smt. Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Minister of Finance,
Govt. of India, New Delhi.

Room No. 501, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi – 110 001, Tel.: 011-23710121, 23711252 (O), 23719023 (F)
E-mail: nitin.gadkari@nic.in, website-www.morth.nic.in
Camp Office Nagpur : Plot No. 25, Opp. Orange City Hospital, Beside Jupiter School, Khamla Chowk, Nagpur-440015(MS)
Tel.: 0712-2239918/20/22/23/24 Email : office@nitingadkari.net

पहली तिमाही में 20 फीसदी बढ़ा कंपनी का मुनाफा, नतीजे जारी होने के बाद शेयर में भी तेजी

MM Q1 Result महिंद्रा एंड महिंद्रा (MM) ने चालू कारोबारी वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जून तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किये हैं। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 फीसदी बढ़कर 3,283 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। वहीं, कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 2,745 करोड़ रुपये रहा।

अगर रेवेन्यू की बात करें तो जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 10 फीसदी की बढ़त के साथ 37,218 करोड़ रुपये रहा। यह एक साल पहले की समान अवधि में 33,892 करोड़ रुपये था।

हमने वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में सभी व्यवसायों में मजबूत परिचालन प्रदर्शन के साथ की है। लीडरशिप की स्थिति का लाभ उठाते हुए ऑटो और फार्म ने बाजार हिस्सेदारी और लाभ मार्जिन का विस्तार जारी रखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में परिवर्तन का परिणाम मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट में सुधार हो रहा है और टेक-महिंद्रा में परिवर्तन मुख्य फोकस के रूप में मार्जिन के साथ शुरू हुआ है।

शेयर की परफॉर्मेंस

आज कंपनी के शेयर 2,937 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुले थे, लेकिन तिमाही नतीजों आने के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। करीब 1.40 बजे कंपनी के शेयर 2,975 .40 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया था। लेकिन, बाद में कंपनी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली।

3 बजे के करीब 3.50 रुपये या 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 2,918.60 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 97.68 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर 76.57 फीसदी चढ़ें हैं।

FY25 में जीडीपी ग्रोथ होगी 7.5 प्रतिशत के करीब, Ind-Ra ने अपने पूर्वानुमान में किया संशोधन

परिवहन विशेष न्यूज

Ind-Ra ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। Ind-Ra को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 3 साल के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा जो वित्त वर्ष 2023-2024 में 4 प्रतिशत था। कहा गया है कि बजट से GDP को रफ्तार मिलेगी।

नई दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। खपत मांग में सुधार की उम्मीद होने से ये फैसला लिया गया है।

विकास गति को मिली बजट से रफ्तार

रिसर्च में कहा गया है कि सरकारी पूंजीगत व्यय, कॉरपोरेट्स/बैंकों की बैलेंस शीट में कमी और निजी कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडीचर की शुरुआत के कारण जारी विकास की गति को अब केंद्र सरकार के बजट से समर्थन मिला है। बजट में कृषि/ग्रामीण खर्च को बढ़ावा देने, एमएसएमई को ऋण वितरण में सुधार और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया है।

GDP में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करते हुए कहा कि Ind-Ra का मानना है कि इन उपायों से खपत मांग को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। Ind-Ra का विकास अनुमान आरबीआई के अनुमान से अधिक है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था और वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण ने 6.5-7 प्रतिशत के बीच सकल घरेलू उत्पाद के विस्तार का अनुमान लगाया था।

2025 में पीक पर पहुंचेगी GDP Growth

Ind-Ra को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 3 साल के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में 4 प्रतिशत था। खपत की मांग अत्यधिक विषम है, क्योंकि यह उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से प्रेरित है।

Ind-Ra ने कहा, "हालांकि, सामान्य से अधिक मानसून और वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में घोषित उपायों से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाकर इसे ठीक करने की उम्मीद है।"

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट में किया बड़ा बदलाव, सितंबर से लागू होंगे नए नियम

परिवहन विशेष न्यूज

Ind-Ra ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। Ind-Ra को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 3 साल के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा जो वित्त वर्ष 2023-2024 में 4 प्रतिशत था। कहा गया है कि बजट से GDP को रफ्तार मिलेगी।

नई दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। खपत मांग में सुधार की उम्मीद होने से ये फैसला लिया गया है।

विकास गति को मिली बजट से रफ्तार

रिसर्च में कहा गया है कि सरकारी पूंजीगत व्यय, कॉरपोरेट्स/बैंकों की बैलेंस शीट में कमी और निजी कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडीचर की शुरुआत के कारण जारी विकास की गति को अब केंद्र सरकार के बजट से समर्थन मिला है। बजट में कृषि/ग्रामीण खर्च को बढ़ावा देने, एमएसएमई को ऋण वितरण में सुधार और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया है।

GDP में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करते हुए कहा कि Ind-Ra का मानना है कि इन उपायों से खपत मांग को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। Ind-Ra का विकास अनुमान आरबीआई के अनुमान से अधिक है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था और वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण ने 6.5-7 प्रतिशत के बीच सकल घरेलू उत्पाद के विस्तार का अनुमान लगाया था।

2025 में पीक पर पहुंचेगी GDP Growth

Ind-Ra को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 3 साल के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जो वित्त वर्ष 2024 में 4 प्रतिशत था। खपत की मांग अत्यधिक विषम है, क्योंकि यह उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से प्रेरित है।

Ind-Ra ने कहा, ₹हालांकि, सामान्य से अधिक मानसून और वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में घोषित उपायों से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाकर इसे ठीक करने की उम्मीद है।₹

प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लंबी कतारों में लगने की नहीं जरूरत, UTS App से चुटकी में बुक हो जाएगी टिकट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के साथ उनके परिजनों को भी सुविधा देने के लिए यूटीएस ऐप (UTS App) लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप यूटीएस ऐप पर कैसे टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे की किस ऐप पर क्या सुविधा मिल रही है?

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ उनके परिजनों का भी ध्यान रखता है। भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rule) के अनुसार अगर आप अपने किसी परिजन को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए स्टेशन जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेनी होगी। अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी लंबी कतारें है।

ऐसे में लंबी लाइन को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने UTS App लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से कुछ मिनटों में ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। इस ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट के साथ जनरल टिकट भी खरीदा जा सकता है।

टिकट बुक करने का प्रोसेस

सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में UTS App को इंस्टॉल करें।

अब होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करें।

इसके बाद यहां आपको अपना नाम, मोबाईल नंबर, DOB, जेंडर दर्ज आदि डिटेल्स देनी होगी।

अब मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करने के बाद लॉग-इन करें।

इसके बाद आपको अपने अनुसार टिकट बुक करना है।

प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना होगा और फिर वॉलेट में रिचार्ज करके आसानी से पेमेंट करना होगा।

पेमेंट होने के बाद आपको Show Ticket में आपको अपना टिकट शो होगा।

NTES ऐप की लें मदद

लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप NTES (National Train Enquiry System) App की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, सफाई आदि कई चीजों पर शिकायत दर्ज करने के लिए आप RailMadad app 'रेल मदद' का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मारुति सुजुकी ने जारी किये पहली तिमाही के नतीजे, नेट-प्रॉफिट 47 फीसदी बढ़ा

शेयर बाजार बंद होने के बाद मारुति सुजुकि इंडिया ने जून तिमाही के नतीजे जारी किये। कंपनी ने बताया कि पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 फीसदी बढ़ा है। वहीं कंपनी के एक्सपोर्ट सेल और नेट सेल में भी इजाफा हुआ है। आज मारुति सुजुकि इंडिया के शेयर 3 फीसदी चढ़कर बंद हुए हैं।

नई दिल्ली। बाजार बंद होने के बाद ऑटोमाबाइल सेक्टक की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकि इंडिया (Maruti Suzuki India) ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के अनुसार कॉस्ट में कमी के प्रयासों, अनुकूल कमोडिटी कीमतों और फॉरेन कैपिटल गेन के कारण कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन शानदार रहा। आज कंपनी के शेयर 3 फीसदी चढ़कर बंद हुए हैं।

मारुति सुजुकि इंडिया तिमाही नतीजा

नेट प्रॉफिटः कंपनी ने बताया कि पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 47 फीसदी बढ़कर 3,650 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बताया कि अकाउंट का कॉस्ट रिडक्शन, कॉमोडिटी प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज गेन में बढ़ोतरी ने कंपनी के मुनाफे में तेजी लाने में मदद की है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,485 करोड़ रुपये था।

नेट सेलः एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार जून तिमाही में कंपनी की नेट बिक्री बढ़कर 33,875 करोड़ रुपये हो गई। यह एक साल पहले की अवधि में 30,845 करोड़ रुपये थी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने बताया कि पहली तिमाही के दौरान 5,21,868 व्हीकल बेचे, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा है।

डोमेस्टिक मार्केट सेलः कंपनी ने कहा कि उसने पहली तिमाही में डोमेस्टिक मार्केट में 4,51,308 यूनिट बेचीं, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4 फीसदी ज्यादा है।

एक्सपोर्ट सेलः अप्रैल-जून तिमाही में एक्सपोर्ट बिक्री 70,560 यूनिट रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 12 फीसदी अधिक है।

शेयर की परफॉर्मेंस

आज के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। बाजार बंद होते समय मारुति सुजुकि के शेयर 501.35 रुपये या 3.8 फीसदी की तेजी के साथ 13,375.00 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। वहीं एक साल में कंपनी ने निवेशकों को 36.19 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर में 31.30 फीसदी की तेजी आई है।

'केवल चार देशों के पास है एडवांस अलर्ट सिस्टम'

वायनाड भूस्खलन आपदा पर बोले अमित शाह- एक हफ्ते पहले दी थी राज्य सरकार को चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वायनाड भूस्खलन आपदा को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने एक हफ्ते पहले ही केरल सरकार को संभावित आपदा के बारे में अलर्ट किया था लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि भारत के पास आपदाओं से बचने के लिए एडवांस अलर्ट सिस्टम है जोकि दुनिया में केवल चार देशों के पास ही।

नई दिल्ली। केरल में भू-स्खलन से हुई तबाही और मौतों के लिए केंद्र पर तोहमत थोपने वाले विपक्षी दलों व सदस्यों को तब मुंहकी खानी पड़ी, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि केरल को एक सप्ताह पहले ही एक नहीं तीन बार बार चेतावनी भेजी गई कि वहां भारी बारिश हो सकती है और यह तक बता दिया गया भूस्खलन भी हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी भेज दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने आपदा की अर्ली वार्निंग के लिए बहुत विकसित व्यवस्था तैयार की है, जो गिने चुने देशों के पास है। पूर्व में कई राज्यों ने वार्निंग का फायदा उठाकर जानें बचाई भी हैं, लेकिन केरल में जो हुआ वह दुखद है।

अमित शाह ने दिया आरोपों का जवाब

मंगलवार को शाह ने दोनों सदनों में अपना बयान दिया। दरअसल कई सदस्यों की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र ने राज्य को चेतावनी क्यों नहीं भेजी थी। शाह ने कहा कि 26 जुलाई को भेजी गई चेतावनी साफ कहा गया था कि केरल में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी और इससे भूस्खलन होने की भी आशंका है। इसमें मलबा बहकर आ सकता है और उसमें दबकर लोग मर भी सकते हैं। इतने स्पष्ट वार्निंग के बावजूद केरल की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

सिर्फ चार देशों के पास है प्रणाली: अमित शाह

शाह ने बताया कि अर्ली वार्निंग देने वाले दुनिया में सिर्फ चार देश है, जिनमें भारत एक है। इसमें भारी वर्षा, तेज गर्मी, तूफान और चक्रवात के लिए दी जाती है। यहां तक कि बिजली गिरने की घटना के लिए अर्ली वार्निंग का सिस्टम है, जो दो घंटे पहले जिलाधिकारी को अक्षांश-देशांतर रेखा के साथ अलर्ट करती है। पूर्व में सात दिन पहले ओडिशा को चक्रवात का अलर्ट भेजा गया था, जिस पर तत्कालीन नवीन पटनायक की सरकार ने काम किया और सिर्फ एक व्यक्ति की मौत, वो भी गलती से हुई।

केरल सरकार को दिया सहयोग का भरोसा

उन्होंने बताया कि इसी तरह से गुजरात सरकार को तीन दिन पहले चक्रवात का अलर्ट भेजा और वहां एक पशु भी नहीं मरा। सभी राज्यों को जानकारी भेजी जाती है, लेकिन कोई काम ही न करे तो केंद्र क्या कर सकता है। हालांकि अमित शाह ने दोहराया कि भारत सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार के साथ डटकर खड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के राज्यों को राहत आपदा कोष से खर्च करने का अधिकार नहीं होने के आरोपों को भी अमित शाह ने गलत बताया।

एसडीआरएफ फंड से जुड़े आरोपों को बताया गलत

उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ से कोई भी राज्य 10 फीसद अपने अनुसार खर्च कर सकता है। बाकी 90 फीसद खर्च उसे आपदा राहत कोष की गाइडलाइंस के अनुरूप करना होता है, लेकिन इतनी निगरानी तो रखनी पड़ेगी कि आपदा के पैसे कहीं और खर्च नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल को आपदा राहत कोष से धन नहीं मिलने के आरोपों को भी उन्होंने खारिज कर दिया।

गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच पश्चिम बंगाल को आपदा राहत के लिए 6244 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। लेकिन जैसे-जैसे खर्च का हिसाब आता है, वैसे-वैसे पैसे रिलीज होते हैं। इसमें से 4619 करोड़ रुपये रिलीज किया जा चुका है। लेकिन वहां समस्या हिसाब का है। उन्होंने साफ किया कि फंड रिलीज तय नियमों के अनुरूप ही हो सकता है और इसके लिए राज्य को हिसाब तो देना ही पड़ेगा।

पेड़ों की कटाई और मूसलाधार बारिश से भरभराया पहाड़, देश में भूस्खलन प्रोन जिलों में वायनाड का 13वां स्थान

केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को विभिन्न पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अबतक 158 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 200 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं 1200 बचावकर्मी मौके पर तैनात हैं और लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके पीछे का कारण मूसलाधार बारिश को बताया जा रहा है।

नई दिल्ली। केरल में भीषणतम प्राकृतिक आपदा आने के कारणों में उसके पर्वतीय इलाके के पर्यावरण से छेड़छाड़ होना प्रमुख है। अव्वल तो वायनाड और आसपास के जिले अत्यधिक भूस्खलन वाले जोन में आते हैं। उस पर से जिन इलाकों में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है, शहरीकरण और पर्यटन क्षेत्र के चलते वहां के जंगल ही साफ किए जा चुके हैं। उस पर से तीव्रतम मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी को कई जगहों से बेहद कमजोर कर दिया।

वर्ष 2021 के स्प्रिंगर के प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न घाट में स्थित केरल के पर्वतीय इलाके भूस्खलन के हाटस्पाट हैं, जहां तकरीबन हर साल ही भूस्खलन होते हैं। लेकिन इस बार की त्रासदी जैसी पहले कभी नहीं हुई। वेस्टर्न घाट में स्थित केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टयम, वायनाड, कोझिकोड और मल्लापुरम जिले सबसे संवेदनशील हैं। इसरो की ओर से पिछले साल जारी 'लैंडस्लाइड एटलस' के अनुसार भारत के तीस सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में दस केरल में हैं।

देश के इन 30 जिलों में वायनाड का स्थान 13वां

देश के इन 30 जिलों में वायनाड का स्थान 13वां है। केरल के जिन 59 प्रतिशत इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, वह खेती वाले इलाके हैं। इसके अलावा, वर्ष 1950 से 2018 के बीच वायनाड जिले के 62 प्रतिशत जंगल साफ हो गए हैं। करीब 1800 प्रतिशत हरियाली का सफाया हुआ है। इसके अलावा, वायनाड में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में 140 मिमी बरसात हुई।

'300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई'

कुछ इलाकों में तो इसी अवधि में 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। लिहाजा, मूसलाधार ने केरल को सबसे भीषण आपदा से रूबरू कराया। केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के एसिस्टेंट प्रोफेसर केएस सजिनकुमार ने बताया कि इस पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ पर दो तरह की परतें हैं। सख्त चट्टानों के ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ी रहती है, लेकिन भारी वर्षा से मिट्टी में नमी भर जाती है और उसका पानी से फूलकर पर्वतीय चट्टानों से फिसलना और धंसना शुरू हो जाता है।

'वे जजों-सैनिकों और अधिकारियों की जातियां पूछते हैं', भाजपा का कांग्रेस से सवाल- जनगणना कैसे होगी?

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना की मांग को लेकर संसद में तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वह गणना की बात करता है। अनुराग के इस तंज पर संसद से सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तमतमा गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता भी कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करने में जुट गए।

नई दिल्ली। सड़क से संसद तक विपक्ष द्वारा उठाई जा रही जातिगत जनगणना की मांग के बीच भाजपा सांसद द्वारा राहुल गांधी की जाति पूछ लिए जाने से कांग्रेस आक्रोशित है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रतिप्रश्न किए गए हैं।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो व्यक्ति हिन्दुस्तान में सबकी जाति पूछ सकता है, उसकी जाति पूछने में क्या गड़बड़ी है? साथ ही पूछा कि यदि जाति पूछना अपमान है तो वह जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे?

बिना नाम लिए बात कही तो एक को ही बुरा क्यों लगा?

भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में संबित पात्रा ने कहा कि जब से 18वीं लोकसभा शुरू हुई है, तब से 99 की संख्या और अहंकार का खेल दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का व्यवहार और उसके कारण उनकी पार्टी के सदस्यों का व्यवहार अक्षम्य है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जब अपना विषय रखा तो किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वह गणना की बात कर रहे हैं तो

एक ही व्यक्ति को बुरा लगा, जबकि सदन में 543 सदस्य हैं।

'वे अधिकारियों की पूछते हैं जाति'

भाजपा प्रवक्ता ने कहा पिछले दिनों राहुल गांधी पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि हलवा समारोह में किस-किस जाति के अधिकारी हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि वे जजों-सैनिकों की जातियां भी पूछते हैं और कहते हैं कि देश को जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'कांग्रेस के सदस्यों ने संसद में चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि यह पवित्र सदन है, यहां किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। जब सदन में नहीं पूछी जा सकती तो बाहर कैसे पूछी जा सकती है? क्या ये धरती पवित्र नहीं है, सिर्फ सदन ही पवित्र है?'

पात्रा ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का कुत्सित प्रयास राहुल गांधी ने किया। साथ ही दावा किया कि पूर्व के चुनावों में जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए थे, तब मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर में अपना धर्म गैर-हिंदू लिखवाया था।

बजट में नाम पर बवाल, राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर क्या बोलीं वित्त मंत्री?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में बजट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और इस साल राज्यों को ज्यादा बजट आवंटित किया गया है।

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राज्यों को कम आवंटन अथवा उनके साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख रुपये दिए जाने हैं और यह राशि पिछले साल के मुकाबले 2.49 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।

वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सभी सेक्टरों पर आवंटन बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के समय इन सभी क्षेत्रों को दिए गए पैसों से तुलना करते हुए बताया कि मोदी सरकार में सामाजिक क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च बढ़ता ही जा रहा है।

'जिक्र न होने का मतलब भेदभाव नहीं'

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को इस बार 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 8000 करोड़ रुपये अधिक है, जबकि संप्रग सरकार ने 2013-14 के बजट में कृषि को केवल 30,000 करोड़ रुपये दिए थे। वित्त मंत्री ने दोहराया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र नहीं होने का यह मतलब नहीं होता कि उसे आवंटन नहीं किया गया।

उन्होंने संप्रग सरकार की अवधि में दस सालों के दौरान पेश किए गए बजटों को याद करते हुए बताया कि एक बार 26 राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे। गौरतलब है कि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही ध्यान दिया है, क्योंकि उसके लिए जदयू और तेलुगु देसम पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है और इन दलों को खुश करने की कोशिश की गई है।

भेदभाव के आरोपों को बताया बेबुनियाद

गैर भाजपा दलों के शासन वाले राज्यों के साथ सौतेले व्यवहार के आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त ऋण देने के मामले में भेदभाव की केरल सरकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा था कि केरल सरकार अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी। राज्यसभा में वित्त मंत्री का जवाब लोकसभा (लगभग पौने दो घंटे) में उनके संबोधन के मुकाबले करीब आधे घंटे लंबा था और इसमें मुख्य रूप से आर्थिक सवालों के जवाब अधिक थे।

वित्तीय घाटे पर विपक्षी नेताओं की चिंता का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 2025-26 तक घाटे को 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। सीतारमण के अनुसार बजट में विकास, रोजगार, कल्याणकारी खर्च, पूंजीगत निवेश और खजाने के प्रबंधन के बीच बेहतरीन संतुलन कायम किया गया है। संप्रग सरकार के दस सालों में पूंजीगत खर्च के लिए आवंटन 13.19 लाख करोड़ रुपये था, जबकि मोदी सरकार के दस वर्षों में यह 43.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

'अग्निवीर योजना पर न हो राजनीति'

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में आज 97 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। यह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमारी प्रगति को दर्शाता है। पिछले साल 30 प्रतिशत मोबाइल फोन निर्माण निर्यात के लिए था। वित्त मंत्री ने विपक्ष को यह नसीहत भी दी कि वह अग्निवीर योजना को लेकर कोई राजनीति न करे, क्योंकि यह योजना देश के सशस्त्र बलों को युवा बनाने के साथ ही युद्ध के लिए सदैव तैयार रखने के लिए लाई गई है।

विपक्ष की ओर से इस योजना की आलोचना को पूरी तरह खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि 17.5 से 21 वर्ष की आयु वाले युवाओं की सेना में नियुक्ति से देश को फिट सैनिक मिलेंगे। हमें इस योजना को लेकर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर वह योजना है, जिसे हम पूरी तरह सोच-समझकर लाए हैं।

ओड़शिा में बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनके माता-पिता जेल जाएंगे

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा, भुबनेस्वर: साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर भी रोक रहेगी। अगर ये बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनके माता-पिता जेल जाएंगे। साथ ही, संबंधित बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर माता-पिता या अभिभावक गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल होगी और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सोमवार से राज्य भर में विशेष धरपगढ़ अभियान शुरू किया गया है. प्रदेश के 35 एआरटीओ और 3 एआरटीओ के तहत अगले 3 दिनों तक अभियान जारी रहेगा। पहले दिन कुल 153 मामले दर्ज किये गये और 60 वाहन जब्त किये गये।

मन को सत्संग से ही आराम मिलेगा स्वामी रामप्रकाश

परिवहन विशेष न्यूज

बेंगलूरू: सीरवी समाज एच.एस.आर. लेआउट में चल रहे चातुर्मास के दसवे दिन में कथा का वाचन करते हुए स्वामी रामप्रकाश जी महाराज ने बताया की जैसे तन को घर में आराम मिलता है, वैसे ही मन को सत्संग में ही आराम मिलेगा. उन्होंने कहा यदि आपके मन में सच्ची लालसा है, तड़प है तो आपको सत्संग एवं महात्माओं के सानिध्य का आशीर्वाद जरूर मिलेगा. हर क्षण आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है. हर बात के लिए परमात्मा का आभार मानिये. स्वामी जी कहा एक नारी को विनम्रता एवं सादगी का उदाहरण होना चाइए. एक महात्मा को आदर्श पुरुष होना चाइए. एक राजा को शक्तिशाली होना चाइए. एक साझेदार व्यापारी को एक-दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाइए. उन्होंने कहा कि अपने मन के दास नहीं- मन के मालिक, अनुशासक होना चाइए। स्वामी जी ने बताया जब हमारी अन्तर की आँखे खुलेंगी, तभी हम बनावटी स्वपनो की दुनिया से बाहर आ पाएंगे. तभी हमें यह अनुभव होगा कि- जो कुछ हम देख रहे थे वो केवल एक सपना है, छलावा है. वर्तमान में इस स्वपनावस्था में हम सोचते है कि जो कुछ हम अनुभव करते है, देख रहे हैं, वही सत्य हैं, पर वो सत्य नहीं है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मांगीलाल चोयल, कोषाध्यक्ष भंवरलाल बर्फा, नारायणलाल सोलंकी, नेमाराम परिहारारिया, ताराराम राठौड़, नवयुवक मण्डल सदस्य भंवरलाल गेहलोत, मोहनलाल राठौड़ आदि उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023